

वर्ष 12 • अंक 214 • 14 पृष्ठ

• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

एक नज़र

मारुति: छूट, कम मार्जिन से बढ़ेगी परेशानी

यात्री वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजूकी के सितंबर 2019 तिमाही के वित्तीय नतीजे काफी हद तक बाजार के अनुमानों के अनुरूप रहे। गुरुवार को घोषित दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी के राजस्व में 25 फीसदी कमी दर्ज की गई। इसी तरह, बिक्री में भी 30 प्रतिशत कमी देखी गई। प्रति वाहन औसत राजस्व या प्राप्तियों में सुधार के कारण बिक्री के मुकाबले राजस्व में कम गिरावट दर्ज की गई।

पृष्ठ 2

बीएसएनएल-एमटीएनएल खर्च करेंगी 11,000 करोड़

हाल में घोषित पुनरुद्धार पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है। इन कंपनियों को इन सेवाओं का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये निवेश करने होंगे। इसके साथ ही पहले चरण की संपत्ति मुद्रीकरण की कवायद से बीएसएनएल को अपने 14,000 करोड़ रुपये कर्ज निपटाने में मदद मिलेगी।

पृष्ठ 4

इंडियाबुल्स समूह के खिलाफ हो रही जांच

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसे इंडियाबुल्स गुप के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा कि इंडियाबुल्स वेंचर लिमिटेड (आईबीवीएल), इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईबीएचएफएल) और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट्स लिमिटेड (आईबीआर्इएल) की जांच चल रही है। सरकार ने कहा कि आईबीवीएल और आईबीएचएफएल के बारे में जांच रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक और आईबीआर्एल पर रिपोर्ट नवंबर के अंत तक तैयार हो जाएगी।

चिदंबरम 30 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम से पृछताछ की अनुमति दी और कहा कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जटिलता के मामले में उन्हें तुरंत एम्स ले जाया जाए। उनकी हिरासत की अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो पहले थीं।

आज का सवाल	
क्या न्यायालय का आदेश दूरसंचार कंपनियों का बिगाड़ेगा कारोबार	
www.bshindi.com पर राय भेजें। <p>आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।</p>	
पिठले सवाल का नतीजा	
क्या एमटीएनएल-बीएसएनएल वित्तय से सुधरेंगे हालात	हां 36.36% <p>नहीं 63.64%</p>

कारोबारी सुगमता में लंबी छलांग

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

भारत कारोबारी सुगमता की विश्व रैंकिंग में 14 स्थान की छलांग के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व बैंक की इस रैंकिंग में भारत ने 2017 में 30 और 2018 में 23 स्थान की छलांग लगाई थी। विश्व बैंक द्वारा आज जारी ‘डूइंग बिज़नेस 2020’ में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर है। पिछले साल वह 77वें स्थान पर था। कारोबारी सुगमता के मामले में भारत दो साल पहले शीर्ष 100 देशों की फेहरिस्त में शामिल हुआ था। तब वह 30 स्थान की छलांग के साथ 130 से 100वें स्थान पर पहुंचा था। विश्व बैंक ने भारत को उन अर्थव्यवस्थाओं के शामिल किया है, जिन्होंने लगातार तीसरे साल अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। इन देशों में भारत के साथ सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, पाकिस्तान और चीन भी शामिल

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अरवबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com



►► पृष्ठ 6

उपहार में सोने का सिक्का चित

संजीव पुरी ►► पृष्ठ 2

अनुमान से बेहतर रहा आईटीसी का मुनाफा



डॉलर रु. 71.90 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 79.00 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38296 ▲ 18 रुपये | सेंसेक्स 39020.40 ▼ 38.40 | निफ्टी 11582.60 ▼ 21.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 11611.20 ▲ 28.50 | ब्रैट वूड 60.40डॉलर ▼ 0.10 डॉलर

दूरसंचार कंपनियों को झटका

उच्चतम न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व पर स्वारिज की याचिका

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को आज तगड़ा झटका लगा, जब उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विभाग द्वारा तय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुआई वाले तीन सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग द्वारा तय परिभाषा को बरकरार रखने के साथ यह भी कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अब तक बकाया शुल्क पर जुर्माना और ब्याज भी चुकाना होगा।

न्यायालय ने कहा, ‘अगर शुल्क बकाया रह गया है तो समझौते के मुताबिक उस पर 50 फीसदी जुर्माना देना होगा। इसलिए हमें यह दलील समझ नहीं आती कि ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज नहीं वसूले जा सकते। इन परिस्थितियों में हमें यह राशि माफ करने या कम करने का कोई आधार नजर नहीं आता।’ अदालत ने यह भी कह दिया कि इस मामले में अब कोई और मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और वह एजीआर की गणना करेगी तथा और कंपनियों को उसका भुगतान करने के लिए समयसीमा भी तय करेगी।

न्यायालय का फैसला आने के बाद बंबई स्टॉक एक्सचेंज में भारती एयरटेल के शेयर में 10 फीसदी और वोडाफोन आइडिया के शेयर में 24 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि दिन के अंत में भारती एयरटेल का शेयर 3.31 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ, लेकिन वोडाफोन आइडिया का शेयर 23.36 फीसदी गिरकर बंद हुआ। भारती एयरटेल पर

	(करोड़ रुपये में)	
	2017-18	2018-19
सकल राजस्व	245980	224243
एजीआर	150423	138635
एबिटा	33775	30550
पीएटी	१50436	36033
स्रोत: सीओआईआई एबिटा और पीएटी केवल मोबाइल सेवाओं के लिए 2018-19 के लिए एबिटा और पीएटी अनुमानित हैं क्योंकि बीएसएनएल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं		

लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 21,700 करोड़ रुपये का बकाया है और वोडाफोन आइडिया पर करीब 28,300 करोड़ रुपये का बकाया है। दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस पर लाइसेंस शुल्क का 16,500 करोड़ रुपये बकाया है। एजीआर की अवधारणा 1999 की नई दूरसंचार नीति से अस्तित्व में आई। नीति में सुझाव दिया गया था कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां फिक्स्ड लाइसेंस शुल्क की व्यवस्था से राजस्व साझेदारी शुल्क व्यवस्था में जा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल संचार सेवा प्रदाताओं को उन्हें आवंटित स्पेक्ट्रम की रेडियो फ्रीक्वेंसी के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भी भुगतान करना होता है। यह व्यवस्था उस समय संकट में आ गई, जब दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने एजीआर की परिभाषा को ही चुनौती दे डाली। दूरसंचार विभाग ने उस समय

लाभांश आय, लघु अवधि के निवेश पर ब्याज आय, कॉल पर छूट, अलग से लाइसेंस लेकर चलने वाली गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत रीडर्बसमेंट को एजीआर के दायरे में शामिल किया था। टीडीसैट ने विभाग द्वारा तय एजीआर की परिभाषा के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों की याचिका सुनने के बाद मामला ट्राई के पास भेज दिया था।

इस बीच भारती एयरटेल ने कहा, ‘दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। यह फैसला उस वक्त आया है, जब क्षेत्र गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।’

वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह फैसले का अध्ययन कर रही है और तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक आधार पर गुंजाइश देखी तो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी।

इन्फोसिस की बड़ीं मुश्किलें

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 24 अक्टूबर

संकट में आई सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज इन्फोसिस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के बाद अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनियम आयोग (एसईसी) ने भी कंपनी के खिलाफ शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने भी हाल में गठित ऑडिट नियामक नैशनल फाइनैसिंग रिपोर्टिंग ऑथॉरिटी (एनएफआरए) को आज कंपनी के खिलाफ गलत लेखा गतिविधियों की शिकायत की जांच करने का आदेश दे दिया।

अमेरिका की एक अदालत में कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया गया है। इन्फोसिस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह पूरी ताकत के साथ अपना बचाव करेगी। एक्सचेंज को भेजी रिपोर्ट में कंपनी ने कहा, ‘अज्ञात व्हिसलब्लोअर की शिकायतों के बाद कंपनी एसईसी के संपर्क में है। उसे पता चला है कि एसईसी ने उसके खिलाफ जांच शुरू की है। कंपनी इस जांच में सहयोग

करेगी।’ कंपनी ने यह भी बताया कि सेबी ने शिकायतों के संबंध में उससे अतिरिक्त जानकारी मांगी हैं। इन्फोसिस ने कहा कि वह बाजार नियामक के आग्रह के अनुरूप जरूरी जानकारी मुहैया

कराएगी। इस बीच नियामकों की पैनी नजर और नकारात्मक खबरों के बीच इन्फोसिस को दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला से कुछ बल मिला। झुनझुनवाला ने कहा कि ये आरोप कंपनी की छवि खराब करने के लिए लगाए गए हैं। एक निजी टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ‘व्हिसलब्लोअर की शिकायत बिल्कुल बेबुनियाद है। सेबी को ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उस दिन हुए सभी कारोबार की जांच करनी चाहिए। शिकायतों में दम होना चाहिए मगर कंपनी के खिलाफ दर्ज शिकायत कोई खास मंशा पूरी करने के लिए आई है।’

उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी की जांच करना कोई मामूली बात नहीं होगी और इसमें समय लगेगा।

महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन वापस, हरियाणा में आगे

अर्चिस मोहन

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एकतरफा जीत के दावे किए जा रहे थे लेकिन आज आए नतीजे पार्टी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। करीब 150 दिन पहले हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा और सहयोगी दलों ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाताओं ने उसे झटका दे दिया।

भाजपा का चुनावी प्रचार मुख्य रूप से अनुच्छेद 370 खत्म करने के इर्दगिर्द था लेकिन मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी। इन चुनावों से विपक्ष खासकर कांग्रेस के दिग्गज मजबूत बनकर उभरे हैं। शरद पवार तथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे क्षेत्रीय नेताओं के राजनीतिक करियर को संजीवनी मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी ने इन राय्यों में साफ सुथरी सरकार दी है।

उन्होंने कहा कि पार्टी दोनों राय्यों के विकास के लिए काम करती रहेगी। हरियाणा में पार्टी को पिछली बार से तीन फीसदी ज्यादा वोट मिले लेकिन वह बहुमत से दूर रह गई। मनोहर लाल खट्टर सरकार के नौ मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस ने इसे भाजपा की नैतिक हार बताया और

हरियाणा			
कुल सीट: 90			
पार्टी	सीटें	2014 में सीटें	
भाजपा	40	47	
कांग्रेस	31	15	
जेजेपी	10	--	
आईएनएलडी	01	19	
निर्दलीय/अन्य	08	09	
महाराष्ट्र			
कुल सीट: 288			
भाजपा	103	122	
शिवसेना	57	63	
राकोंपा	53	41	
कांग्रेस	46	42	
अन्य	29	20	
स्रोत: चुनाव आयोग की वेबसाइट			

विपक्षी दलों से हरियाणा में मिलकर सरकार बनाने की अपील की। हालांकि भाजपा राज्य में निर्दलीयों और छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। भाजपा ने 90 सदस्यीय हरियाणा में 40 सीटें जीती हैं और उसे बहुमत के लिए छह विधायकों की जरूरत है। महाराष्ट्र में भाजपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि शिवसेना ने 124 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।

■ **शेष पृष्ठ 14**

2 कंपनी समाचार

खबरों में रहे स्टॉक



टॉट फार्मास्युटिकल्स

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 44 फीसदी बढ़ा

₹ 1,680.70 पिछला बंद भाव
₹ 1,766.95 आज का बंद भाव
▲ 5.13 %

एचसीएल टेक्नोलॉजिज

एक पर एक बोनस शेयर, 100 फीसदी अंतरिम लाभांश की सिफारिश

₹ 1,095.65 पिछला बंद भाव
₹ 1,118.55 आज का बंद भाव
▲ 2.09 %

पीआई इंडस्ट्रीज

प्रबंधन ने दूसरी छमाही के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई

₹ 1,332.20 पिछला बंद भाव
₹ 1,425.90 आज का बंद भाव
▲ 7.03 %

पॉलिकैब इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 66 फीसदी बढ़ा

₹ 782.15 पिछला बंद भाव
₹ 826.75 आज का बंद भाव
▲ 5.70 %

कर्मिस इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 27 फीसदी घटा

₹ 578.70 पिछला बंद भाव
₹ 546.25 आज का बंद भाव
▼ 5.61 %

संक्षेप में

ओयो होटल जापान में 50 नए होटल जोड़ेगी

होटल नेटवर्क कंपनी ओयो ने गुरुवार को कहा कि जापान में उसका संयुक्त उद्यम अप्रैल 2020 तक अपनी विस्तार योजनाओं के तहत 50 और होटल जोड़ने की योजना बना रहा है। ओयो होटल्स जापान, ओयो और सॉफ्टबैंक ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसके मौजूदा समय में वहां 100 होटल हैं। इसने अप्रैल में अपना परिचालन शुरू किया था। ओयो होटल्स जापान ने अप्रैल 2020 तक आओमोरी, असाहिकावा, फूफेकी और अन्य शहरों में 50 और होटल जोड़ने की योजना बनाई है।

भाषा

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शुद्ध लाभ बढ़ा

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही में 14 फीसदी बढ़कर 48.82 करोड़ रुपये हो गया। आईईएक्स ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 42.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। उसकी आय 2019-20 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 78.71 करोड़ रुपये पहुंच गई जो एक साल पहले इसी तिमाही में 75.21 करोड़ रुपये थी।

भाषा

आरएनएएम का कर बाद मुनाफा 21 फीसदी बढ़ा

रिलायंस निप्पॉन लाइफ ऐसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 21 फीसदी बढ़कर 137 करोड़ रुपये हो गया। आरएनएएम ने गुरुवार को शेयर बाजारों को नियामकीय सूचना में कहा है कि कंपनी ने एक साल पहले 113.07 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय एक साल पहले की समान अवधि के 424 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 322.60 करोड़ रुपये रह गई।

भाषा

मारुति: छूट, कम मार्जिन से चिंता

बिक्री में भारी गिरावट से मुनाफे पर चोट, सितंबर तिमाही में 30 फीसदी घटी बिक्री

राम प्रसाद साहू और अरिंदम मजूमदार
मुंबई, 24 अक्टूबर

यात्री वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजूकी के सितंबर 2019 तिमाही के वित्तीय नतीजे काफी हद तक बाजार के अनुमानों के अनुरूप रहे। तिमाही के दौरान कंपनी के राजस्व में 25 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई जबकि बिक्री में 30 फीसदी की गिरावट रही। प्रति वाहन औसत राजस्व अथवा प्राप्तियों में सुधार के कारण बिक्री के मुकाबले राजस्व में कम गिरावट दर्ज की गई। बीएस6 वाहनों के लिए कीमत बढ़ाए जाने से कंपनी की प्राप्तियों में सुधार हुआ।

कंपनी ने कहा है कि मंदी के अलावा वाहन उद्योग में बिक्री घटने का एक प्रमुख कारण लागत में वृद्धि है। सुरक्षा मानदंडों को लागू किए जाने, बीमा लागत में वृद्धि और कुछ राज्यों में सड़क कर में इजाफे के कारण वाहनों की लागत बढ़ी है। अधिक डाउन पेमेंट के कारण वाहनों की फाइनेंसिंग संबंधी समस्याओं से भी तिमाही के दौरान बिक्री प्रभावित हुई। यात्री वाहन श्रेणी में लगातार पांचवीं तिमाही के दौरान बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है।

मारुति के वित्तीय नतीजे



■सितंबर के दौरान मारुति सुजुकी के राजस्व में 25 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई

■कंपनी ने कहा है कि उद्योग में बिक्री घटने का एक प्रमुख कारण लागत में वृद्धि है

एक पर एक बोनस शेयर, 100 फीसदी अंतरिम लाभांश की सिफारिश

₹ 1,095.65 पिछला बंद भाव

₹ 1,118.55 आज का बंद भाव

▲ 2.09 %

पीआई इंडस्ट्रीज

प्रबंधन ने दूसरी छमाही के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई

₹ 1,332.20 पिछला बंद भाव

₹ 1,425.90 आज का बंद भाव

▲ 7.03 %

पॉलिकैब इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 66 फीसदी बढ़ा

₹ 782.15 पिछला बंद भाव

₹ 826.75 आज का बंद भाव

▲ 5.70 %

कर्मिस इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 27 फीसदी घटा

₹ 578.70 पिछला बंद भाव

₹ 546.25 आज का बंद भाव

▼ 5.61 %

इंडिगो का नुकसान बढ़कर 1,031 करोड़ रुपये

सबसे बड़ी देसी विमानन कंपनी इंडिगो का परिचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का कर पूर्व नुकसान सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 1,031 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसकी वजहों में मार्क टु मार्केट विदेशी विनियम नुकसान व विमान रखरखाव खर्च के लिए प्रावधान शामिल हैं। पिछले साल की समान अवधि में विमानन कंपनी का कर पूर्व नुकसान 987 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने सालाना

₹ 1,332.20 पिछला बंद भाव
₹ 1,425.90 आज का बंद भाव
▲ 7.03 %

पीआई इंडस्ट्रीज

प्रबंधन ने दूसरी छमाही के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई

₹ 1,332.20 पिछला बंद भाव
₹ 1,425.90 आज का बंद भाव
▲ 7.03 %

पॉलिकैब इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 66 फीसदी बढ़ा

₹ 782.15 पिछला बंद भाव
₹ 826.75 आज का बंद भाव
▲ 5.70 %

कर्मिस इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 27 फीसदी घटा

₹ 578.70 पिछला बंद भाव
₹ 546.25 आज का बंद भाव
▼ 5.61 %

नई दिल्ली | 25 अक्टूबर 2019 शुक्रवार

खसतौर से ग्रामीण इलाकों में चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद आईटीसी लिमिटेड का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 37 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4,174.69 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी को सरकार की तरफ से की गई कर कटौती का फायदा मिला और इसने लाभ में योगदान किया। कंपनी का मुनाफा बाजार अनुमान से बेहतर रहा। बाजार को आईटीसी के शुद्ध लाभ में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद थी।

₹ 782.15 पिछला बंद भाव
₹ 826.75 आज का बंद भाव
▲ 5.70 %

पीआई इंडस्ट्रीज

प्रबंधन ने दूसरी छमाही के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई

₹ 1,332.20 पिछला बंद भाव
₹ 1,425.90 आज का बंद भाव
▲ 7.03 %

पॉलिकैब इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 66 फीसदी बढ़ा

₹ 782.15 पिछला बंद भाव
₹ 826.75 आज का बंद भाव
▲ 5.70 %

कर्मिस इंडिया

दूसरी तिमाही में कर पूर्व मुनाफा 27 फीसदी घटा

₹ 578.70 पिछला बंद भाव
₹ 546.25 आज का बंद भाव
▼ 5.61 %

अनुमान से बेहतर रहा आईटीसी का मुनाफा

अभिषेक रक्षित

कोलकाता, 24 अक्टूबर

खासतौर से ग्रामीण इलाकों में चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद आईटीसी लिमिटेड का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 37 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4,174.69 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी को सरकार की तरफ से की गई कर कटौती का फायदा मिला और इसने लाभ में योगदान किया। कंपनी का मुनाफा बाजार अनुमान से बेहतर रहा। बाजार को आईटीसी के शुद्ध लाभ में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद थी।

कंपनी की कुल आय 6.62 फीसदी बढ़कर 13,497.27 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि सकल लाभ 11.32 फीसदी बढ़कर 5,042.11 करोड़ रुपये रहा। गौर करने लायक बात यह है कि कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ में अंतर 867.42 करोड़ रुपये का है।

आईटीसी ने कहा, 31 मार्च 2019 को टाली गई कर देनदारी और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में कर खर्च के अनुमान का फिर से आकलन किया गया है



और मौजूदा व बाकी बची तिमाही में पड़ने वाले उसके असर की पहचान की गई है। इसके परिणामस्वरूप दूसरी तिमाही के कर खर्च में 349.62 करोड़ रुपये का क्रेडिट शामिल है। एडलवाइस सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष अवनीश रॉय ने कहा, सिगरेट की बिक्री में अनुमानित तौर पर तीन फीसदी की बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुल राजस्व में इसकी हिस्सेदारी 43.28 फीसदी रही।

कंपनी का एफएमसीजी कारोबार करीब 4.02 फीसदी बढ़कर राजस्व के लिहाज से 3,296.22 करोड़ रुपये रहा। हालांकि लाइफस्टाइल रिटेलिंग कारोबार को छोड़ दें तो इस क्षेत्र का एबिटा 39 फीसदी बढ़कर 221 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन में 170 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई। इस श्रेणी में सकल रास्व 52.26 फीसदी बढ़कर 92.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

इंडिगो का नुकसान बढ़कर 1,031 करोड़ रुपये

सबसे बड़ी देसी विमानन कंपनी इंडिगो का परिचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का कर पूर्व नुकसान सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 1,031 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसकी वजहों में मार्क टु मार्केट विदेशी विनियम नुकसान व विमान रखरखाव खर्च के लिए प्रावधान शामिल हैं। पिछले साल की समान अवधि में विमानन कंपनी का कर पूर्व नुकसान 987 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने सालाना

आधार पर परिचालन राजस्व में 31 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 8,105 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, लेकिन नतीजे पर मार्क टु मार्केट विदेशी विनियम पर 425 करोड़ रुपये के नुकसान का असर पड़ा।

पीएनबी हाउसिंग का लाभ बढ़ा

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शुद्ध लाभ चालू

वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 45 फीसदी बढ़कर 366.8 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी को 253 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 2,230.34 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,808.26 करोड़ रुपये रही थी।

बीएस

डीएचएफएल के परिसमापन के विकल्प पर विचार कर रहे लेनदार

हंसिनी कार्तिक

मुंबई, 24 अक्टूबर

दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर बढ़ती कयासबाजी को देखते हुए लेनदार अपना बकाया वसूलने के लिए वैकल्पिक तरीका अपनाने पर विचार कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, अपना बकाया कर्ज को डीएचएफएल की इक्विटी में बदलने के मामले में लेनदार सतर्क हो गए हैं।

ऐसे में समझा जाता है कि लेनदार कंपनी से अपना बकाया वसूलने के लिए प्लान-बी पर काम कर रहे हैं और इसके तहत वे अपना बकाया वसूलने के लिए डीएचएफएल के परिसमापन या उसकी परिसंपत्तियां खरीदने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। एनसीडी समेत बैंकों का कुल बकाया 47,000 करोड़ रुपये है जबकि सुरक्षित लेनदारों मसलन म्युचुअल फंडों व खुदरा एनसीडीधारकों का करीब 17,000 करोड़ रुपये बकाया है। डीएचएफएल के पास 90,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां हैं और उसके खाते में खुदरा होमलोन की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है।

एक सूत्र ने कहा, लेनदार अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कंपनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपना बकाया वसूलने के लिए वैकल्पिक उपायों पर फैसला अगले दो या तीन हफ्तों में होगा जब बैंक डीएचएफएल को दिए कर्ज पर प्रावधान करना शुरू करेंगे। डीएचएफएल को ज्यादातर बैंकों ने सितंबर तिमाही तक मानक परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत किया है, वहीं दिसंबर तिमाही में यह स्थिति बदल सकती है जब बैंकों को डीएचएफएल के कर्ज के हिसाब से 15 फीसदी प्रावधान करना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि गैर-लेनदारों ने बैंकों को अपनी सहमति दे दी है कि सभी लेनदारों के बकाए के निपटान के लिए डीएचएफएल की परिसंपत्तियों का परिसमापन

समाधान की तलाश



■ लेनदार अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर कंपनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं

■ अपना बकाया वसूलने के लिए वैकल्पिक उपायों पर फैसला अगले दो या तीन हफ्तों में होगा जब बैंक डीएचएफएल को दिए कर्ज पर प्रावधान करना शुरू करेंगे

■ एनसीडी समेत बैंकों का कुल बकाया **47,000** करोड़ रुपये है जबकि सुरक्षित लेनदारों मसलन म्युचुअल फंडों व खुदरा एनसीडीधारकों का करीब **17,000** करोड़ रुपये बकाया है

निश्चित रूप से होना चाहिए। म्युचुअल फंड हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब तक डीएचएफएल की परिसंपत्तियों की बिक्री से मूलधन का उचित हिस्सा मिल जाएगा तो हमारे लिए यह ठीक रहेगा।

एक सूत्र ने कहा, समझा जाता है कि बैंक अब अपने बकाए का एक हिस्सा इक्विटी में बदलने के मामले में चिंतित हो गए हैं। जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती कि दिलचस्पी वाले प्राइवेट इक्विटी निवेशक की तरफ से बैंक की डीएचएफएल में हिस्सेदारी कर्ज को इक्विटी में बदलने के 6 से 9 महीने के भीतर नहीं खरीदने की पुष्टि नहीं होती, बैंक प्रस्तावित समाधान योजना पर अपनी सहमति शायद नहीं देंगे।

प्रस्तावित समाधान योजना के मुताबिक, बैंक अपने बकाए का दो फीसदी इक्विटी में बदलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से करीब 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज इक्विटी में बदलेगा। बैंकों

ने डीएचएफएल को दिलचस्पी रखने वाले पीई फर्म से बातचीत करने को कहा है कि यह रकम (6,000 करोड़ रुपये) एस्क्रो खाते में जमा कराई जानी चाहिए कि निवेशक ने डीएचएफएल की बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी से बाध्यकारी करार कर लिया है।

बैंक इस पर सहमत हैं कि पीई निवेशक व डीएचएफएल के बीच सौदे की शर्तें कुछ निश्चित दृष्टांत के साथ हो और वे उनके कारोबार को विनियमित करने में मदद के इच्छुक हैं। लेकिन वे निवेशक से सही मायने में प्रतिबद्धता चाहते हैं।

पहले खबर मिली थी कि एयॉन कैपिटल डीएचएफएल की 51 फीसदी हिस्सेदारी लेने की इच्छुक है। हालांकि संपर्क किए जाने के बाद एयॉन कैपिटल ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। डीएचएफएल से जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब भी नहीं मिला।

अंकेक्षकों की भूमिका जांचेगा सेबी, आरबीआई

नियामक जांच करेंगे कि डीएचएफएल की रकम की हेराफेरी वर्षों तक कैसे छुपी रही

देव चटर्जी

मुंबई, 24 अक्टूबर

बाजार नियामक सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक यह समझने के लिए अंकेक्षण फर्म टी पी ओस्तवाल की राय जानने की योजना बना रहा है कि ऑडिट फर्म ने इस साल मार्च में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) को कैसे क्लिन चिट दे दी, जब मीडिया वेबसाइट कोबरापोस्ट ने खुलासा किया था कि डीएचएफएल के प्रवर्तकों ने कंपनी से रकम की हेराफेरी की है।

कोबरापोस्ट के खुलासे के कुछ ही दिन के भीतर ओस्तवाल को डीएचएफएल बोर्ड में नियुक्त किया गया था। ओस्तवाल की रिपोर्ट 5 मार्च को डीएचएफएल ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा किया और तब से डीएचएफएल का शेयर लगातार टूट रहा है और उसके शेयरधारकों ने 86 दिन हुई गिरावट के कारण अपने बाजार कीमत में 3,600 करोड़ रुपये गंवा दिए।

जुलाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू हुए फॉरेंसिक ऑडिट और केपीएमजी के फॉरेंसिक ऑडिट में पुष्टि हुई कि प्रवर्तकों ने 20,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है और कई मामलों में डीएचएफएल की तरफ से 40 इकाइयों को दी गई उधारी का सही रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। नियामक डेलांयट की भी राय चाहेगा जो 2015 से 2019 के दौरान डीएचएफएल की अंकेक्षक थी, जब फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था। संपर्क किए जाने पर ओस्तवाल ने टिप्पणी करने से मना कर दिया।

अपनी रिपोर्ट में टी पी ओस्तवाल एंड एसोसिएट्स ने 26 संबंधित इकाइयों को 11,520

डीएचएफएल : घटनाक्रम

जनवरी 2019 : कोबरापोस्ट ने डीएचएफएल पर रकम की हेराफेरी का आरोप लगाया, डीएचएफएल ने इसकी जांच के लिए स्वतंत्र अंकेक्षक की नियुक्ति की

मार्च 2019 : ऑडिट फर्म टी पी ओस्तवाल ने डीएचएफएल व प्रवर्तकों को क्लीन चिट दी

जुलाई 2019 : बैंकों ने वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2019 के डीएचएफएल के खाते के अध्ययन के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया

अक्टूबर 2019 : केपीएमजी ने डीएचएफएल से रकम की हेराफेरी की पुष्टि की

करोड़ रुपये कर्ज दिए जाने के मामले में क्लीन चिट दी है। टी पी ओस्तवाल एंड एसोसिएट्स ने रिपोर्ट में कहा है, कंपनी ने कथित तौर पर 26 मुखौटा कंपनियों का प्रवर्तन नहीं किया है, जो उसके कर्जदार हैं। इसके अलावा उन इकाइयों में प्रवर्तक समूह के सदस्य समेत कोई भी एकसमान निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा कंपनी या प्रवर्तकों के पास इन कंपनियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, न ही ये इकाइयां कंपनी की शेयरधारक हैं। इसके मुताबिक आरोपों की पुष्टि करने के लिए संकेतक नहीं हैं कि कंपनी ने रकम की हेराफेरी के लिए मुखौटा कंपनियों का गठन किया। जून में हॉन्ग कॉन्ग की शोध फर्म

रीड इंटेलिजेंस ने कहा कि संबंधित पक्षकारों को दिए गए फंड छुपाने के लिए डीएचएफएल समेत कई भारतीय एनबीएफसी ने बॉक्स कंपनियां गठित की। 7 जून की रिपोर्ट में रीड इंटेलिजेंस ने कहा कि अन्य एनबीएफसी ने भी कर्ज के रोलओवर के लिए ऐसे ही ढांचे का इस्तेमाल किया और प्राधिकरण या शेयरधारकों को इसकी सूचना नहीं दी, जो सेबी व आरबीआई के खुलासा नियमों का उल्लंघन है।

डीएचएफएल के मामले में तीन बॉक्स कंपनियां हैं – हेमिस्फेयर, गैलेक्सी और सिलिकन। तीन बॉक्स कंपनियों के पास मार्च 2018 में डीएचएफएल के 3.11 करोड़ शेयर यानी डीएचएफएल की करीब 9 फीसदी हिस्सेदारी थी और इन शेयरों को बाजार में बेच दिया गया। पूरे साल तीनों कंपनियों ने शेयर बेचे और इस तरह से जून के आखिर तक 40 लाख शेयर निपटाए और सितंबर तक उनकी हिस्सेदारी 76.5 लाख शेयर और कम हो गई, साथ ही मार्च 2019 तक रजिस्टर में यह नजर नहीं आया।

रीड ने कहा कि जब कंपनियां ऐसे ढांचे का इस्तेमाल करती हैं तब खाता बही की जांच करने वाले अंकेक्षकों के लिए इसके वास्तविक लाभार्थी का पता लगाना मुश्किल होता है।

उसने कहा है कि डीएचएफएल ने चार छद्म कंपनियों अलीन रियल एस्टेट डेवलपर्स, एडविना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, नोशन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और प्रशूल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 2,000 करोड़ रुपये उधार दिए। इन कंपनियों ने बाद में दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे, जो वधावन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक है और इसका स्वामित्व संस्थापकों के पास है।

बीमा फर्मों के शेयरों पर विदेशी निवेशकों का तेजी का नजरिया

दीपक कोरगांवकर

और पुनीत वाधवा

मुंबई/नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने

हाल में समाप्त तिमाही में बीमा कंपनियों के शेयर खरीदे हैं और इस अवधि में इन कंपनियों में उनकी

हिस्सेदारी 1 से चार फीसदी तक बढ़ी है। कैलेंडर वर्ष 2019 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एफपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 23.72 फीसदी पर पहुंच गई, जो दिसंबर 2018 की तिमाही के आखिर में 4.87 फीसदी थी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में

उनकी हिस्सेदारी 12.22 फीसदी से बढ़कर 20.84 फीसदी और एचडीएफसी लाइफ में 8.23 फीसदी से बढ़कर 15.94 फीसदी पर पहुंच गई। आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

इन शेयरों पर एफपीआई के तेजी के नजरिये के कारण इनमें इस

साल अब तक एक्सचेंजों में 50 से 65 फीसदी तक की बड़ोतरी दर्ज हुई है।बीएसई पर इनमें से ज्यादातर शेयर अभी अपने-अपने सर्वोच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इसकी तुलना में एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इस अवधि में 8 फीसदी उछला है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों को

भरोसा है कि आगामी दिनों में भारत की जीवन बीमा कंपनियां नए कारोबारी में मजबूती दर्ज करेगी और इनके बढ़त का परिदृश्य आगामी 10 वर्षों के लिए बेहतर है। हालांकि निकट भविष्य में उन्हें नए कारोबार की कीमत में नरमी की संभावना है क्योंकि प्रीमियम

की रफ्तार में नरमी शुरू हो गई है।

2019 में अच्छी खासी तेजी के बावजूद निवेश रणनीति के तौर पर हालांकि ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों का नजरिया इन शेयरों को लेकर तेजी का है और उनका सुझाव है कि लंबी अवधि के लिए निवेशक इन शेयरों को गिरावट में खरीदें।

मशीनीकृत कोयला परिवहन पर बड़ा निवेश करेगी कोल इंडिया

कोल इंडिया ने अपनी बड़ी खदानों से पाइप्ड कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयले के पूरी तरह से मशीनीकृत परिवहन पर अगले पांच साल में अनुमानित तौर पर 17,500 करोड़ रुपये निवेश करेगी। साल 2023–24 तक होने वाला यह काम सड़क के जरिए कोयले के परिवहन को पूरी तरह से बदल देगा। कुछ खदानों में यह व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे नहीं अपनाया गया है। इसे कोल इंडिया की 35 परियोजनाओं में चालू किया जाएगा।

बीएस

4 विविध समाचार

4जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगी सरकारी कंपनियां

मेघा मनचंदा

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

हाल में घोषित पुनरुद्धार पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने का फैसला किया है, जिसे देखते हुए कंपनियों को इन तेज रफ्तार सेवाओं का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये निवेश करने होंगे।

इसके साथ ही पहले चरण की संपत्ति मुद्रीकरण की कवायद से बीएसएनएल को अपने 14,000 करोड़ रुपये कर्ज निपटाने में मदद मिलेगी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'यह निवेश (4जी स्पेक्ट्रम बुनियादी ढांचे के लिए) आंतरिक स्रोतों से आएगा और अगले 2 साल में इसे खर्च किया जाएगा।'

संकट में फंसी इन दो सरकारी कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें इक्विटी शेयर के रूप में 14,115 करोड़ रुपये और तरजीही शेयर के रूप में एमटीएनएल को 6,295 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है।

मुद्रीकरण के लिए 38,000 करोड़ रुपये की रियल एस्टेट संपत्तियों की पहचान की जाएगी। इस संपत्ति में प्राथमिक रूप से जमीन के साथ किराये और पट्टे वाले भवन शामिल हैं। एमटीएनएल के सिर्फ दिल्ली में ही 29 खुदरा आउटलेट हैं।

केंद्र सरकार ने दो बीमार इकाइयों के लिए 70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही दोनों इकाइयों का विलय किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि दोनों कंपनियां रणनीतिक रूप से अहम हैं। इनकी बिक्री या बंदी नहीं की जाएगी।

हाल की रिपोर्टों में कहा गया था कि कुछ प्रमुख मंत्रालयों की राय थी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का पुनरुद्धार व्यावहारिक नहीं है और इन्हें बंद किया जा सकता है।

राहत पैकेज में 15,000 करोड़ रुपये का सांवरिन बॉन्ड जारी किया जाना शामिल है। साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासित मूल्य पर किया जाएगा, जो 2016 की नीलामी के मूल्य पर आधारित होगा।

दो कंपनियों को 20,140 करोड़ रुपये का 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। साथ ही इन कंपनियों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए 29,937 करोड़ रुपये और 3,674 करोड़ रुपये वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए आवंटित किए गए हैं, जो रेडियोवेव्स के आवंटन पर लगेंगे। वीआरएस योजना को अंतिम रूप दोनों कंपनियां देंगी। जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल या उससे ऊपर है, उन्हें एकमुश्त राशि देकर स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति का हिस्सा बनाने के लिए 17,169 करोड़ रुपये बजट समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा पेंशन संबंधी लाभ के भुगतान के लिए 12,768 करोड़ रुपये की जरूरत है।

कर्ज घटने से वृद्धि सुस्त : फिच

अभिजित लेले

मुंबई, 24 अक्टूबर

भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) से कर्ज बढ़े पैमाने पर कम हुआ है। कुल नई उधारी 2019-20 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद- (जीडीपी) का 6.6 प्रतिशत हो सकती है, जो 2018-19 में 9.5 प्रतिशत थी। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक इन अनुमानों से पता चलता है कि पूरे साल तक उधारी सुस्त रही।

भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून 2019 (जून तिमाही) में लगातार 5वें महीने सुस्त रही। सालाना आधार पर जून महीने में जीडीपी का विस्तार सिमटकर 5 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले के 8 प्रतिशत की तुलना में कम है। यह 2013 के बाद की सबसे सुस्त वृद्धि दर है। फिच ने एक बयान में कहा है कि यह कमजोरी व्यापक है, जिसमें घरेलू व्यय और बाहरी मांग गति खो रही है।

फिच ने कहा, ‘हम उम्मीद



2019-20 में नई उधारी की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत हो सकती है

करते हैं कि 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि 5.5 प्रतिशत रहेगी। जबकि 2020-21 में 6.2 प्रतिशत और 2021-22 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगले 2 साल तक वृद्धि दर क्षमता से कम रहने की संभावना है।’

एनबीएफसी पिछले डेड़ साल से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उन्होंने तेजी से वाणिज्यिक क्षेत्र की कर्ज देना कम कर दिया है। एनबीएफसी द्वारा कर्ज कम किए

सुरजीत दास गुप्ता

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

उच्चतम न्यायालय के दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ आदेश से दूरसंचार बाजार के निजी क्षेत्र की दो कंपनियों की ओर बढ़ने की संभावना है। इस फैसले से जहां रिलायंस जियो को भारी लाभ होगा, जिसे अपनी दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में बहुत मामूली राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

इससे सरकार को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाने के संकट से जूझ रही है। इस फैसले से सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व मिल जाएगा।

बहरहाल सरकार को इसका कितना लाभ मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उच्चतम न्यायालय कंपनियों को इस राशि का भुगतान कितने समय में करने को कहता है। यह फैसला न्यायालय को करना है। साथ ही अपार सरकार दूरसंचार कंपनियों को कुछ वित्तीय छूट देने को तैयार है, जिससे कि वे अपने बकाये

रोमिता मजुमदार और राम प्रसाद साहू

मुंबई, 24 अक्टूबर

दूरसंचार क्षेत्र की मुश्किलें खत्म होती

नजर नहीं आ रही हैं। गुरुवार को आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने इन कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर अदालत का फैसला इन कंपनियों के खिलाफ आया है जिसके बाद उन्हें इस मद में 92,641 करोड़ के बकाये का भुगतान करना होगा।

लंबे वक्त से एजीआर की परिभाषा को लेकर दूरसंचार कंपनियाँ और दूरसंचार विभाग के बीच विवाद बना हुआ था। दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्कों को राजस्व हिस्सेदारी के तौर पर सरकार को देती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो राजस्व की वह रकम जिसका उपयोग इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिा की जाती है एजीआर कहलाता है। जबकि दूरसंचार विभाग मानता है कि बैंक जमाओं आदि जैसे स्रोतों से अर्जित आय को भी एजीआर में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जबकि दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि इसके लिए केवल प्रमुख दूरसंचार सेवाओं से अर्जित आय पर ही विचार किया जाना चाहिए।

उद्योग के साझेदारों ने इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उनका कहना

का भुगतान सरकार को कर सकें तो वह स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए दो साल का वक्त दे सकती है।

इससे उद्योग पर कितना गंभीर असर पड़ेगा, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि पिछले वित्त वर्ष में इस उद्योग का कुल राजस्व 2,61,991 करोड़ रुपये था। लेकिन समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) महज 1,80,728 करोड़ रुपये और ईबीआईडीटीए सिर्फ 53,953 करोड़ रुपये था। यह राशि उसकी आधी है, जितना शीर्ष न्यायालय ने भुगतान करने का आदेश दिया है। और इसमें ब्याज भुगतान का बोझ शामिल नहीं है, जो 4,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज पर करना है।

साफ है कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (वीआईएल) को सबसे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसे सबसे ज्यादा 28,308 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल नहीं है, जिसका भुगतान कंपनी को करना है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर नजर आया, जिसमें आज 26.55 प्रतिशत की तेज

एजीआर पर आदेश से कंपनियों को इटका

रोमिता मजुमदार और राम प्रसाद साहू

दूरसंचार क्षेत्र की मुश्किलें खत्म होती

नजर नहीं आ रही हैं। गुरुवार को आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने इन कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर अदालत का फैसला इन कंपनियों के खिलाफ आया है जिसके बाद उन्हें इस मद में 92,641 करोड़ के बकाये का भुगतान करना होगा।

लंबे वक्त से एजीआर की परिभाषा

को लेकर दूरसंचार कंपनियाँ और दूरसंचार विभाग के बीच विवाद बना हुआ था। दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्कों को राजस्व हिस्सेदारी के तौर पर सरकार को देती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो राजस्व की वह रकम जिसका उपयोग इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए की जाती है एजीआर कहलाता है। जबकि दूरसंचार विभाग मानता है कि बैंक जमाओं आदि जैसे स्रोतों से अर्जित आय को भी एजीआर में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जबकि दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि इसके लिए केवल प्रमुख दूरसंचार सेवाओं से अर्जित आय पर ही विचार किया जाना चाहिए।

उद्योग के साझेदारों ने इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उनका कहना

का भुगतान सरकार को कर सकें तो वह स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए दो साल का वक्त दे सकती है। इससे उद्योग पर कितना गंभीर असर पड़ेगा, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि पिछले वित्त वर्ष में इस उद्योग का कुल राजस्व 2,61,991 करोड़ रुपये था। लेकिन समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) महज 1,80,728 करोड़ रुपये और ईबीआईडीटीए सिर्फ 53,953 करोड़ रुपये था। यह राशि उसकी आधी है, जितना शीर्ष न्यायालय ने भुगतान करने का आदेश दिया है। और इसमें ब्याज भुगतान का बोझ शामिल नहीं है, जो 4,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज पर करना है।

साफ है कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (वीआईएल) को सबसे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसे सबसे ज्यादा 28,308 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल नहीं है, जिसका भुगतान कंपनी को करना है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर नजर आया, जिसमें आज 26.55 प्रतिशत की तेज

उच्चतम न्यायालय के आदेश से जियो को मिला बल



गिरावट हुई है और इसकी बाजार पूंजी 12,300 करोड़ रुपये कम हुई है। यह राशि उस राशि की आधी है, जिसका भुगतान करने को उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने डीओटी की मांग के एवज में सिर्फ 10,771

■न्यायालय के फैसले के बाद सबसे कम भुगतान रिलायंस जियो को, महज 13 करोड़ रुपये देने होंगे

■वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को सबसे तगड़ा झटका लगा है, जिसे 28,308 करोड़ रुपये भुगतान करना होगा

■इस झटके को भांपकर कंपनी के शेयर 26.55 प्रतिशत गिरे, 12,300 करोड़ रुपये घटी कंपनी की बाजार पूंजी

■भारती एयरटेल को भी 6,000 करोड़ रुपये देने होंगे, लेकिन अगर द्विधुवीय बाजार बनता है तो उसे लाभ होगा

करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि कंपनी की वित्त वर्ष 19 के बैलेंस शीट में शामिल है। कंपनी को न्यायालय के आदेश के बाद जिस राशि का भुगतान करना है, उसकी तुलना में यह एक तिहाई है।

शीर्ष न्यायालय के आदेश के बाद कंपनी एक बार फिर ज्यादा इक्विटी

बकाया है जबकि इस उद्योग में उतरी

सबसे नई कंपनी रिलायंस जियो पर

13 करोड़ रुपये का बकाया है जिसका

भुगतान दूरसंचार विभाग को किया

जाना है।

बाकी 40,540 करोड़ रुपये का बकाया उन कंपनियों पर हैं जो या तो बंद हो चुकी हैं या फिर कर्ज समाधान प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं। इनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 10,456 करोड़ रुपये, एयरसेल पर 7,852 करोड़ रुपये और टाटा टेलीसर्विसेज पर 9,987 करोड़ रुपये का बकाया है। उल्लेखनीय है कि ये कंपनियां बाजार में रिलायंस जियो के कदम रखने के बाद से बंद हुई हैं और बचे हुए परिचालकों को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

92,641 करोड़ रुपये में से केवल 25 फीसदी ही वास्तविक बकाया है। बाकी रकम ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज है।

एमके ग्लोबल के शोध विश्लेषक नवल सेठ ने लिखा, ‘हमारा अभी भी मानना है कि खराब होती वित्तीय सेहत, ग्राहकों की घटती संख्या और एकीकरण में बनी हुई बाधाओं की वजह से वीआईएल एक लचर कंपनी बनी हुई है। वीआईएल पर बड़ी हुई वित्तीय दबाव से भारती और रिलायंस जियो के लिए संभावित दो कंपनियों का अधिकार वाले बाजार के लिए वैकल्पिक मूल्य तैयार होगा जो पहले से ही जारी है।’

बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिंच ने टेलको को खरीद का विकल्प दिया है और कहा है कि तीसरा कमजोर कारोबारी भारती एयरटेल के हिसाब से बेहतर है। इससे कंपनी तेजी से बाजार के राजस्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। भारती की देनदारी करीब 6,000 करोड़ रुपये है, जो इसकी कुल 2,1000 करोड़ रुपये देनदारी (जिसमें एसयूसी शामिल नहीं है) का एक हिस्सा है। यही वजह है कि एयरटेल का शेयर शुरू में तो गिरा, लेकिन बाद में संभल गया।

निश्चित रूप से इस फैसले का सबसे बड़ा लाभार्थी रिलायंस जियो है, जिसे एसयूसी को छोड़कर महज 13 करोड़ रुपये भुगतान करने होंगे। इससे साफ है कि जहां दो प्रतिस्पर्धी ऑपरेटों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, वहीं जियो को इसका लाभ मिलेगा और वह भी भविष्य में कारोबार आकर्षक पाएंगे, खासकर ऐसे समय में जब कंपनी ग्राहक गंवा रही है।

इस फैसले से निश्चित रूप से भारती एयरटेल की वित्तीय स्थिति पर

क्लाउड सर्विस पर आया ट्राई का परामर्श पत्र

नेहा अलावधी

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने क्लाउड सर्विसेज पर परामर्श पत्र जारी कर इस पर विभिन्न हिस्सेदारों से अपना पक्ष रखने को कहा है। प्राथमिक रूप से इसका मकसद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडरों के उद्योग संगठनों के पंजीकरण का ढांचा तैयार करना है, जिसमें एमेज़ॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अजूरै शामिल हैं।

इस परामर्श पत्र में उद्योग संगठन के पंजीकरण की शर्तें, पात्रता, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण की अवधि, प्रशासन का ढांचा व अन्य संबंधित मसले शामिल किए गए हैं, जो उद्योग संगठनों के पंजीकरण के लिए तय किए जाने हैं।

यह परामर्श प्रक्रिया ट्राई की उस कवायद की कड़ी है, जिसके तहत उसने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वह क्लाउड सर्विस प्रोवाइडरों

(सीएसपी) से जुड़े उद्योग संगठनों

के पंजीकरण का व्यापक ढांचा

तैयार करे। ट्राई ने यह परामर्श पत्र

बुधवार को जारी किया है और इस

पर प्रतिक्रिया देने की आखिरी तिथि

20 नवंबर तक की गई है। जवाबी

प्रतिक्रिया दाखिल करने की तिथि

4 दिसंबर तय की गई है।

पत्र में कहा गया है,

‘उद्योग निकायों को

स्थापित करने का

मकसद यह सुनिश्चित

करना है कि उद्योग और

उससे जुड़े उद्योग संगठन

के सदस्यों द्वारा

स्वनियमन की व्यवस्था

बनाई जा सके। इसमें

वर्णित या स्वीकार की गई आचार

संहिता होगी, जिसे उन्हें स्वीकार

करना होगा। यह जरूरी है कि सभी

अहम कारोबारी एक या अन्य उद्योग

निकाय का हिस्सा बनें, अन्यथा

क्लाउड यूजर्स को ढांचे का लाभ

नहीं मिलेगा।’

ट्राई ने प्रस्ताव किया है कि

सीएसपी के लिए उद्योग संगठन

मुनाफे के लिए नहीं होगा, लेकिन

सदस्यों से प्रवेश शुल्क लेने की

इजाजत दी जा सकती है।

भारत से विवाद सुलझाने पर मलेशिया कर रहा काम

रॉयटर्स

क्वालालंपुर, 24 अक्टूबर

कश्मीर मसले पर प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के रुख के बाद मलेशिया भारत के साथ विवादों को सुलझाने पर काम कर रहा है। मलेशिया के वाणिज्य मंत्री ने यह भी उम्मीद है कि 16 देशों के बीच होने वाले कारोबारी समझौते पर इस साल हस्ताक्षर हो जाएंगे। भारत इस समझौता वार्ता में शामिल है और उसने कुछ आपत्तियां उठाई हैं।

महातिर के संयुक्त राष्ट्र में बयान के बाद समझौते को लेकर सुस्ती आ गई थी। पिछले महीने उन्होंने आम सभा में कहा था कि भारत ने कश्मीर में 'आक्रमण किया और कब्जा कर लिया', जो एक मुस्लिम बहुल विवादास्पद क्षेत्र है और उस पर पाकिस्तान भी अपना दावा करता है।

महातिर के इस बयान के बाद भारत के कारोबारियों ने मलेशियाई पाम तेल का बहिष्कार किया, जिसे महातिर ने कारोबारी जंग की तरह



करार दिया। इसके अलावा भारत में यह भी चिंता जताई जा रही है कि क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) पर चल रही बातचीत भी प्रभावित हो सकती है।

गुरुवार को संवाददाताओं से बात करते हुए मलेशिया के आंतरिक व्यापार और उद्योग मंत्री दारेल लेइकिंग ने कहा कि आरसीईपी पर बातचीत पटरी पर है और इसमें एसोसिएशन आफ

साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) के 10 सदस्यों और चीन, भारत, जापान, दक्षिण

कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 6 देशों सहित सभी सदस्य

शामिल होंगे।

आरसीईपी सम्मेलन 4 नवंबर को बैंकॉक में होगा।

लेइकिंग ने कहा कि सम्मेलन के पहले कुछ भी हो

उत्तर प्रदेश

राजस्थान

पंजाब

► **क्षेत्रीय मंडियों के भाव**

कानपुर
गेहूं लूज 2065/2070, जो 1825/1830, चावल मसुरी 2325/2350, चावल मोटा 2225/2250, सरसों 3940/4000, तिल सफेद 9600/9700, सोया (टीन) 1325/1350, तेल सरसों कच्ची घानी वैंट पेड (टीन) 1400/1475, **लखनऊ**
गेहूं, दड़ा 2080/2085, गेहूं शरबती 2750/2900, चावल शरबती सेला 3600/3700, सूरज 4200/4300, लालमती 3200/3300, चावल (सोना) 2800/2850 **चंडौसी**
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1390, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1495, फ्लैक 1430, डीएनओ 976, टरपीन लैंस बोल्ड 1515 **मुजफ्फरनगर**
गुड़ (40 किलो): लहू नया 1100/1180, खुरपा 950/1010,चाकू 980/1125, रसकट 925/930, शक्कर 1225/1250, चीनी मिल डिली. (किंव.) (जीएसटी

अतिरिक्त): खलौली 3440, देववंद 3370, सिडोय 3340, बुढ़ाना 3380, **सपुड़**
गुड़-चीनी: चीनी हजिर 3700/3750, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1025/1040, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंड़ी.) 4075, खल: सरसों 2250/2350, **जयपुर**
अनाज: चावल डीबी 6200/6300, गेहूं (मिल) 2115/2125, मक्की 2175/2180, बाजरा 1720/1725, जौ 1750/1800, ग्वार लूज 3700/3750, ज्वार केटलफ़ीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4340/4350, **श्रीगंगानगर**
गेहूं (डैरी) 2000/2050, ग्वार 3650/3700, जौ 2080/2090, सरसों लूज 3750/3800 **जोधपुर**
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार

डिलीवरी (ऑलपेड) 3950/4000, ग्वाराम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1790/1800, बाजरा (जयपुर) 1775/1780, चना 4200/4300, **यन्ना**
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति किंव.): राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्याइंट)140, राइसब्रान (अखाद्य) 137, खल सरसों 2000, डीओसी: राइसब्रान वेंच सफेद 1650, लाल 1580, कंटीन्यूअस 1600, **लुधियाना**
दाल-दलहन: राजमा चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7300/7800, उड़द साबुत 6000/7000, उड़द धोया 7000/8000, चिलका 7000/7700, दाल मसूर 5250/5500, चनादाल 5300/5550, **अमृतसर**
चावल: वासमती (1121 नं.) 5350/7600/7600, सेला 6400/6500, शरबती साधारण सेला 3500/3600, शरबती स्टीम 4300/4400, बूरा खांड 3600/3700

करनाल
गेहूं दड़ा 2090/2100, वासमती चावल 7400/7500, धान 1121 नं. 3300/3350, पुराा 1509 धान 2650/2750, शरबती धान 2000/2050, सेला नया(1509 नं.) चावल 5050/5150, स्टीम 7500/7600, **हिसार**
ग्वार 3700/3750, सरसों 3850/3900, गेहूं 2090/2100, नरमा कपास 5100/5175 **जौड़**
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 1950/2000, आटा (प्रति 44 किलो) 1050/1070, मैदा 1050/1175, देशी ची (एक ली/जार) 400/470, रिफाइनड (टीन) 1330/1340, **भिवानी**
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3900/3950, खल बिनौला मोटी 3000/3050, बिनौला 3000/3300, सेला 7100/8700,चीन 7400/8100, गेहूं 2100/2150, ग्वार 3650/3750, बाजरा 1800/2000 ***एनएनएस***

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 214

दूरसंचार को एक और झटका

सर्वोच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत देश की शीर्ष दूरसंचार कंपनियों तथा सरकार के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर एक व्यवस्था दी है।

इसका संबंध कंपनियों द्वारा चुकाए जाने वाले शुल्क की प्रकृति से है। अदालत ने सरकार के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा है।

कि कंपनियों को कुल 92,461 करोड़ रुपये सरकार को चुकाने होंगे। दूरसंचार कंपनियों ने कहा है कि स्पेक्ट्रम शुल्क के हिस्से के रूप में सरकार के साथ राजस्व साझेदारी केवल स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से मिले राजस्व तक सीमित होनी चाहिए। सरकार ने जोर दिया है कि अन्य राजस्व मसलन ब्याज या किराये से मिले राजस्व आदि को भी इसमें

शामिल किया जाना चाहिए। यह अतिरिक्त बकाया करीब 23,000 करोड़ रुपये है। सरकार ब्याज, जुर्माना और जुमाने पर ब्याज की मांग भी कर रही है। यह राशि कुल मिलाकर 92,000 करोड़ रुपये हो जाती है। सरकार इस निर्णय से प्रसन्न होगी और राहत महसूस कर रही होगी क्योंकि अतिरिक्त राशि की मदद से उसे अपनी संकट वित्तीय स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। दरअसल इसमें से कुछ राशि का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की सरकारी प्रतिस्पर्धियों बीएसएनएल-एमटीएनएल की स्थिति सुधारने में भी किया जा सकता है।

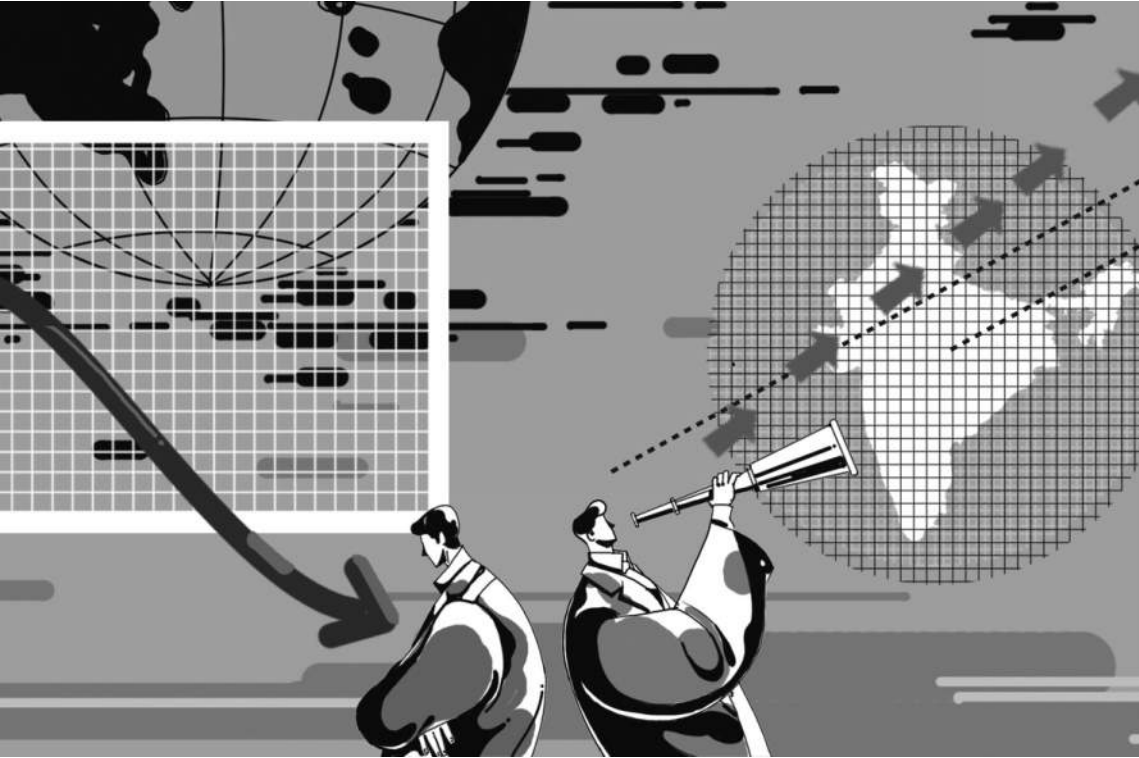
दूसरी तरह से देखें तो यदि सरकार न्यायालय द्वारा दिए गए विकल्प को अपनाती

है तो यह दूरसंचार बाजार पर प्राणांतक वार की तरह होगा। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में भारती एयरटेल पर करीब 1.06 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। कुछ लॉबित स्पेक्ट्रम भुगतान इससे इतर था। इस राशि का आधा हिस्सा अल्पावधि की जवाबदेही था। इसी अवधि में वोडाफोन आइडिया पर कुल 1.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह अतिरिक्त बोझ ऐसे वक्त में आया है जब ये कंपनियां रिलायंस जियो के साथ कीमतों की जंग में उलझी हुई हैं। जियो अपनी सेवाएं घाटे पर देने को तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के पास रिलायंस समूह के पेट्रोकैमिकल व्यवसाय से काफी धन आ रहा है। सरकार को अब यह निर्णय लेना है कि आगे क्या राह है।

उसने विमानन क्षेत्र में जो गड़बड़ी की है उसे दूरसंचार में दोहराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका असर व्यापक होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र पर वित्तीय दबाव बढ़ने से बैंकिंग ऋण चुकाने की उनकी क्षमता भी प्रभावित होगी। सरकार को दूरसंचार क्षेत्र के भविष्य का नए सिरे से आकलन करना चाहिए। सन 2000 के दशक की तरह इसे वृद्धि और उत्पादकता का वाहक होना है या यह भी सरकार के लिए एक दुधारू गाय है जिसका लाभ लोक कल्याण के लिए धन जुटाने में किया जाएगा। यदि दूसरी बात सही है तो सरकार अपना पूरा बकाया मांग सकती है और तब कम से कम एक कंपनी बाजार से बाहर हो जाएगी। परंतु यदि सरकार यह मानती है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

और निवेश को प्राथमिकता देकर इस क्षेत्र की उत्पादकता और वृद्धि में सुधार किया जा सकता है तो उसे अलग तरीके से सोचना होगा। कंपनियों को जल्दी ही 5जी के बुनियादी ढांचे में निवेश आरंभ करना होगा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल भारत का अपना लक्ष्य हासिल करना है तो संचार क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के इर्दगिर्द एक नवाचारी व्यवस्था आरंभ करनी होगी। सरकार की मांग से पहले ही त्रस्त यह क्षेत्र इस बुनियादी ढांचे को आकार देने में सक्षम नहीं है।

अब यह निर्णय सरकार को लेना है कि उसे इस क्षेत्र के साथ कैसा व्यवहार करना है। संभव है वह व्यापक राष्ट्रीय हित को देखते हुए जुर्माना और ब्याज माफ कर दे।



अजय मोहंती

वैश्विक निवेशकों से बातचीत का हासिल

यदि वृद्धि और सुधार के एजेंडे पर ध्यान दिया जाए तो भारत के पास यह अवसर है कि वह चीन की धीमी पड़ती आर्थिक गतिविधियों का लाभ ले सके। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं आकाश प्रकाश

पिछले दिनों मुझे अमेरिका में एक सप्ताह बिताने का अवसर मिला। वहां मैंने सम्मेलनों में हिस्सा लिया और वैश्विक फंड आवंटकों से मुलाकात की। निवेशकों से मुलाकात के लिए यह समय दिलचस्प था। भारत ने हाल ही में कर दरों में कटौती की थी और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आरंभ था। इस यात्रा का हासिल इस प्रकार रहा।

1. भारत को लेकर गहरी रुचि देखने को मिली और लोग यहां के हालात को समझना चाहते थे। ज्यादातर लोग कर कटौती से चकित थे क्योंकि उन्हें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह सवाल भी उठा कि कॉर्पोरेशन कर दर में कटौती क्यों की गई, मांग बढ़ाने के अन्य उपाय क्यों नहीं अपनाए गए। ज्यादातर लोगों की जिज्ञासा थी कि मध्य वर्ग के लिए कर कटौती या कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर का कटौती क्यों नहीं की गई? भारत को बड़ी और उच्च मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुकूल नहीं माना जाता जबकि वही इस कटौती से लाभान्वित हुईं। कुछ लोगों ने पूछा कि कंपनियां कर कटौती का प्रयोग कर नकदी प्रवाह कैसे बढ़ाएंगी? अमेरिका में ज्यादा

कंपनियां पुनर्खरीद या लाभांश के जरिये कर लाभ देती हैं। निवेशक यह जानने को उत्सुक थे कि भारतीय कंपनियां कैसे अलग हैं। भविष्य के सुधार को लेकर उम्मीद नजर आई। सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री को सकारात्मक माना गया। फिर भी अधिकांश लोग यही मान रहे हैं कि भारत एक जटिल स्थान है और इसे कारोबारी दृष्टि से सहज बनाने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है।

2. अधिकांश आवंटकों ने माना कि भारत आर्थिक चक्र के निचले स्तर पर है और पांच फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर खासी नीची रहेगी। अब जबकि राजकोपीय और मौद्रिक दोनों नीतियां काम पर हैं तो अर्थव्यवस्था में सुधार आना चाहिए। एनबीएफसी संकट शुरू हुए भी एक वर्ष हो चुका है और कम ही लोग मानेंगे कि 2020 में वृद्धि दर में सुधार नहीं होगा। राजकोपीय स्थिति को लेकर चिंता थी लेकिन हर निवेशक को लग रहा था कि आरबीआई का वृद्धि और मुद्रास्फीति को समान तवज्जो देने का मौजूदा रुख सही था।

3. इस बात को लेकर चिंता थी कि भारत में कॉर्पोरेट मुनाफे में गिरावट में कमजोरी क्यों है? कई लोगों ने पूछा कि

क्या देश में किसी बड़े बदलाव के कारण कारोबारी मुनाफे में कमी आई है? हर किसी को भारतीय फंड प्रबंधकों के डेटा या उनके आंकड़ों की जानकारी थी। 2008 में भारत और अमेरिका दोनों जगह कारोबारी मुनाफा जीडीपी के लगभग 7.5 फीसदी के बराबर था। आज अमेरिका में वह 10 फीसदी से अधिक है जबकि भारत में घटक 3 फीसदी रह गया है। कर कटौती के कारण सात वर्ष में पहली बार आय में सुधार होगा। निवेशकों ने माना कि मुनाफे में हिस्सेदारी लगातार गिरती नहीं रह सकती। अधिकांश यह मानना चाहते थे कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद कारोबारी मुनाफा सुधरेगा।

4. निवेशक यह मानना चाहते हैं कि देश में आर्थिक और मुनाफे का चक्र दोनों न्यूनतम स्तर पर हैं और अब उनमें केवल सुधार ही हो सकता है लेकिन मूल्यांकन से जुड़ी आशंका के चलते वे देश में निवेश नहीं करना चाहते। एमएससीआई सूचकांक को देखें तो बाजार का मूल्यांकन कमजोर नहीं दिख रहा। कुछ ही लोग सतह के नीचे शेयरों को पहुंचे नुकसान से अवगत थे। मिड कैप सूचकांक जनवरी 2018 के उच्चतम स्तर से 30 फीसदी नीचे हैं जबकि

स्मॉल कैप 40 फीसदी। बाजार के बड़े हिस्से को फिलहाल निवेश योग्य नहीं माना जा रहा। चुनिंदा शेयरों के मूल्य को क्षति पहुंची है। कई शेयर खरीद न होने के कारण नुकसान में हैं। यदि वैश्विक आवंटकों को यह यकीन दिलाया जा सका कि वे शीर्ष 50 कंपनियों से परे निवेश करें तो भारतीय बाजार का मूल्य ठीकठाक है। उस स्थिति में काफी धन आ सकता है।

5. देश के कारोबारी प्रशासन को लेकर निराशा का माहौल था। कई लोग प्रवर्तकों की धोखाधड़ी और बैलेंस शीट की अनियमितताओं को लेकर स्तब्ध थे। वित्तीय सेवा क्षेत्र के कई खुलासे चिंतित करने वाले हैं। आखिर अंकेक्षक, रेटिंग एजेंसियां और नियामक क्या कर रहे थे? ऐसे खुलासे सामने आते रहे तो दिक्कत बढ़ेगी। शेयरों को गिरवी रखने का पैमाना देखकर निवेश चकित थे। कई लोगों ने कहा कि इस संचालन स्तर के साथ भारत महंगे उभरते बाजारों में शामिल नहीं हो सकता।

6. कई आवंटक इस बात से परिचित थे कि भारत एक किस्म की सफाई प्रक्रिया से गुजर रहा है। कई कमजोर कंपनियां और प्रवर्तक समूहों को ढहने दिया जा रहा है। अधिकांश ने माना कि ऐसी सफाई शुरुआत में वृद्धि को धीमा करती है। बहरहाल, आगे चलकर वृद्धि में सुधार होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अधिकांश ने माना कि बीते चार वर्ष में भारत कई आर्थिक झटके झेल चुका है। पहले नोटबंदी, फिर वस्तु एवं सेवा कर और आखिरकार एनबीएफसी संकट। अर्थव्यवस्था के पास सुधारने का अवसर ही नहीं था। आने वाले वर्षों में जरूर हालात सामान्य हो सकते हैं।

7. अधिकांश निवेशक एनबीएफसी संकट की तीव्रता से चकित थे। यह भारत के लिए लीमन ब्रदर्स का ही एक छोटा रूप था। इस संकट ने इस क्षेत्र के अधिकांश थोक कारोबारियों के कारोबारी मॉडल को ध्वस्त कर दिया। अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भरोसे की कमी को देखते हुए आवंटकों को लगा कि आरबीआई को निवेशकों को एनबीएफसी के बहीखातों को लेकर आश्वस्त करना चाहिए था। इससे निवेशकों को काफी मदद मिलती। निजी पूंजी जुटने से ही माहौल में सुधार होगा। निजी पूंजी को रेटिंग एजेंसियां या अंकेक्षकों पर भरोसा नहीं। केवल आरबीआई ही इस गतिरोध को दूर कर सकता है।

8. अधिकांश आवंटकों को यकीन था कि चीन और अमेरिका का तनाव आगे भी बरकरार रहेगा। परिणामस्वरूप चीन में धीमाकरण आया और उसकी अर्थव्यवस्था उच्चतम स्तर देख चुकी है। अधिकांश आवंटक चीन से इतर एशिया के अन्य हिस्सों में अपना निवेश बढ़ाना चाहते थे।

भारत के पास अवसर है कि वह आने वाले वर्ष में निवेश आकर्षित कर सके। निवेशक समझ रहे हैं कि वृद्धि और आय दोनों एकदम निचले स्तर पर हैं। आवंटक धीमी विश्व व्यवस्था में वृद्धि की बात जोह रहे हैं। अधिकांश लोग अभी भी मानते हैं कि लंबी अवधि में देश के पास काफी संभावनाएं हैं। अगर हम स्थिर रहे तो हम लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

दो दशक में भारतीय समाज और राजनीति हो गई ज्यादा संकीर्ण

बीस वर्ष पहले सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एक भारतीय अमर्त्य सेन को मिला था। इस वर्ष एक अन्य भारतवंशी अभिजित बनर्जी को यह सम्मान मिला है। दोनों घटनाओं में दो दशक का अंतराल है लेकिन ऐसा लगता है कि आज का भारत उस वक्त से एकदम अलग है। इस अंतर को दोनों विजेताओं को सम्मानित किए जाने पर सत्ता प्रतिष्ठाान की प्रतिक्रिया से भी समझा जा सकता है। खासतौर पर सत्ताधारी दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बनर्जी को पुरस्कार मिलने पर जो प्रतिक्रिया दी है उससे यह स्पष्ट होता है।

सन 1998 में सेन को सम्मानित करने के नोबेल समिति के निर्णय के बाद चौतरफा सराहना का भाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने सेन को दिए संदेश में कहा था कि यह बेहद नेकनीयत से दिया गया है और उन्होंने कहा कि वह कामना करते हैं कि सेन आगे अकादमिक और शोध कार्य करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने संदेश में कहा कि उन्हें यह सम्मान मिलना राष्ट्रीय गौरव का विषय है। वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी सेन की तारीफ की।

यकीनन बनर्जी को इस वर्ष नोबेल मिलने के बाद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति ने कहा कि बनर्जी के काम ने तमाम अर्थशास्त्रियों को भारत तथा विश्व में गरीबी से लड़ने की बेहतर समझ दी है। मोदी ने गरीबी उन्मूलन में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें बधाई दी। सीतारमण ने भी बनर्जी को गरीबी कम करने में योगदान के लिए बधाई दी।

परंतु सत्ताधारी दल के कुछ अन्य नेताओं के सुर इससे अलग थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने पर बधाई दी लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनकी सोच वाम रुझान वाली है और भारत के लोगों ने उनकी सोच को नकार दिया है। मंत्री का इशारा कांग्रेस द्वारा 2019 के आम चुनाव घोषणा पत्र में पेश न्याय योजना



दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

की ओर था जिसे बनर्जी का समर्थन मिला था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश सिन्हा ने भी बनर्जी के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसकी तुलना सेन से करते हैं। सेन को पुरस्कार मिलने के कुछ ही दिन के भीतर सरकारी विमानन सेवा एयर इंडिया ने जीवन भर की यात्राओं के लिए निःशुल्क पास की पेशकश कर दी थी। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों वित्त सचिव विजय केलकर और मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर एन आचार्य ने उनकी जमकर सराहना की और बधाई दी। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने भी सेन को बधाई दी थी। संक्षेप में कहें तो सन 1998 में 2019 की तरह कोई आलोचना सुनने को नहीं मिली थी।

बीते दो दशक में क्या बदला? सन 1998 में भी भाजपा की सरकार थी और 2019 में भी वही सत्ता में है। सन 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को मोदी की तरह बहुमत हासिल नहीं था। संभव है कि वाजपेयी की सरकार गठबंधन साझेदारों पर बहुत हद तक निर्भर थी। मोदी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। दिलचस्प यह है कि वाजपेयी सरकार का दर्शन भी आज की मोदी सरकार के दर्शन से अलग था। वाजपेयी वैश्विक दृष्टि को लेकर चलते थे। उनकी सरकार आज की तुलना में अधिक समावेशी और सहिष्णु थी। तब तक कि वाजपेयी सरकार के प्रमुख सदस्यों में से एक मुरली मनोहर जोशी ने भी बिना किसी पूर्वग्रह के सेन को बधाई दी थी। ऐसा तब था जबकि सेन उस राजनीतिक फलक से आते थे जिससे उन्हें या उनकी पार्टी को कोई सहानुभूति नहीं थी।

यही कारण है कि रघुराम राजन हों, अरविंद सुब्रमण्यन हों या अभिजित बनर्जी, इन सभी ने खुलकर अपनी बात कही। इनके मन में ऐसी कोई चिंता नहीं थी कि उनके नजरिये से सरकार शर्मिंदा हो सकती है। परंतु सरकार द्वारा ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों को हजम कर पाना हालात को अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाता है। जबकि उसे विचार यह करना चाहिए कि क्या इससे नीति निर्माण में कोई लाभ हो सकता है। यह दुखद है कि सरकार अब तक इस कमजोरी को समझ नहीं पाई है न ही वह आवश्यक संशोधन कर रही है।

कानाफूसी

फिल्मी रास्ता

मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के एक छोटे से कस्बे चंदेरी (साड़ियों के लिए मशहूर) में पर्यटकों की बढ़ती तादाद से उत्साहित मध्य प्रदेश सरकार नई फिल्म नीति लाने की योजना बना रही है ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। यह विचार तब आया जब बॉलीवुड फिल्म स्त्री की कहानी के चंदेरी में केंद्रित होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की तादाद 50,000 का आंकड़ा पार कर गई। फिल्म स्त्री काफ़ी हिट हुई थी और कम बजट में बनी इस फिल्म ने काफी कमाई भी की थी। अधिकारियों का मानना है कि अगर एक फिल्म से क्षेत्र विशेष के पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ सकती है तो इसे बढ़ावा देना आवश्यक है। अब सरकार ने एक समन्वयक की नियुक्ति की योजना बनाई है जो प्रदेश में शूटिंग के लिए आने वाली फिल्म यूनिट का ध्यान रखेगा और उन्हें फिल्मांकन के लिए जगहों के सुझाव भी देगा।

दुविधा निवारक थिंक टैंक

स्वतंत्रता आंदोलन में विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका, अनुच्छेद 370 और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस स्वयं की दुविधा में पा रही है। ऐसे में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन विषयों पर आंतरिक चर्चा के लिए एक थिंक टैंक का गठन किया है। इस 17 सदस्यीय थिंक टैंक की पहली बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। इस दौरान महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी चर्चा होगी। सोनिया और उनके पुत्र राहुल गांधी के अलावा इस थिंक टैंक में शामिल अन्य नेताओं में मनमोहन सिंह,, ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राजीव गौड़ा, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, राजीव साठव और सुष्मिता देव भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस थिंक टैंक में शामिल नहीं हैं।



आपका पक्ष

बैंक घोटाले रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी

लगातार उजागर हो रहे बैंक घोटाले इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में नीतिगत और क्रियाव्यवण स्तर पर कई खामियां हैं। एक आम आदमी को ऋण लेना हो तो तमाम तरह के दस्तावेजों की मांग की जाती है और बैंक के अनेक चक्कर लगाने पड़ते हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद ऋण स्वीकृत होता है। ऋण की एक किस्त चुकाने में अगर देरी हो जाए तो बैंक से फोन आना शुरू हो जाता है। हजारों करोड़ रुपये का ऋण व्यापारियों के लिए आसानी से स्वीकृत होने के बाद वसूल न हो पाना आम आदमी के मन में शंका पैदा करता है। इससे बैंक की नीति और नीयत का संदेह के घेरे में आना स्वाभाविक है। बैंकिंग व्यवस्था को चलाने में आम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन उन्हें ऋण लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जबकि बैंक हजारों करोड़ रुपये का ऋण उद्योगपतियों को आसानी से दे देते हैं। ऋण लेकर कुछ उद्योगपति



विदेश भाग जाते हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या का उदाहरण हमारे सामने है। हाल में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले ने लोगों को फिर सोचने पर मजबूर किया है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रिजर्व बैंक ठीक से निगरानी क्यों नहीं रख पाता है। सवाल यह है कि अनियमितताएं वर्षों तक ऑडिटर की नजर से कैसे

महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक में गड़बड़ी पाए जाने के बाद रुपये की निकासी पर रोक लगी थी

बच जाती है। ऑडिट रिपोर्ट राजनीतिक हस्तक्षेप से भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में निगरानी करने वाली संस्था का ज्यादा मजबूत और

प्रभावशाली होना जरूरी है। बैंकों

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

गरीबों को मिला

आयुष्मान का लाभ

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। आयुष्मान योजना को सफल बनाने में निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग की भी जरूरत है। चिकित्सा पर होने वाले खर्च की वजह से कई लोग अपना कीमती सामान गिरवी रखने से बचे हैं। इसे आयुष्मान भारत की बड़ी सफलता माना जा सकता है। देश के लाखों गरीबों के बीच बीमारियों से मुक्त होने की उम्मीद जगाना भी बड़ी उपलब्धि है। यह सभी नागरिकों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्रीय बिंदु है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर काफी जोर दिया है और इस योजना को शहर से लेकर गांव तक पहुंचाया गया है।

दिवाकर कुमार, मधुपुर

घटेगा सोयाखली का निर्यात

भारी बारिश से सोयाबीन उत्पादन में कमी के कारण मौजूदा तेल विपणन वर्ष में भारत से सोया खली निर्यात 53 प्रतिशत घटकर करीब 10 लाख टन रह सकता है। देश को सोया खली के निर्यात में भारी मूल्य प्रतिस्पर्धा का पहले ही सामना करना पड़ रहा है। प्रसंस्करणकर्ताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के कार्यकारी निदेशक डी एन पाठक ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि जारी तेल विपणन वर्ष 2019-20 (अक्टूबर 2019-सितंबर 2020) में देश से सोया खली निर्यात 10 लाख टन के आसपास रह सकता है। पाठक ने बताया कि भारी बारिश से सोयाबीन पैदावार में गिरावट के कारण घरेलू तेल मिलों में पेराई (तिलहन से तेल निकालने की प्रक्रिया) प्रभावित हो सकती है। इसका स्वाभाविक असर सोया खली उत्पादन पर भी पड़ेगा। सोपा के आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर को समाप्त तेल विपणन वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018-सितंबर 2019) में देश से 21.43 लाख टन का सोया खली निर्यात किया गया था। सोपा के सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक इलाकों में इस बार अगस्त और सितंबर के दौरान मौनसून की भारी बारिश से सोयाबीन की फसल को खासा नुकसान पहुंचा। इस तिलहन की राष्ट्रीय पैदावार करीब 18 प्रतिशत गिरकर 89.94 लाख टन रह सकती है। *भाषा*

कल्याण ज्वैलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याणरम्पण ने कहा कि कल्याण ज्वैलर्स के पास ऑर्डर का आकार सोने से वाउचर में तब्दील हो गया है जिसे भुनाना बहुत आसान होता है। वाउचर से ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पसंद का सरफा या आभूषण खरीदने की छूट मिल जाती है। इस साल हमें कॉरपोरेट वाउचर की बिक्री में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा नजर आया है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Oct 24

International Price %Chg*

Domestic Price %Chg*

METALS (\$/tonne)

Aluminium	1,712.0	-4.7	1,914.7	-8.9
Copper	5,773.0	-3.5	6,096.0	-7.6
Nickel	16,395.0	13.3	17,316.6	20.7
Lead	2,236.0	8.1	2,111.8	-2.9
Tin	16,705.0	-5.4	17,879.8	-4.8
Zinc	2,510.0	2.2	2,660.8	-3.9
Gold (\$/ounce)	1,494.2*	4.8	1,676.9	6.6
Silver (\$/ounce)	17.6*	6.1	19.9	7.6

ENERGY

Crude Oil (\$/bbl)	60.4*	-3.4	60.2	-3.8
Natural Gas (\$/mmBtu)	2.3*	4.5	2.3	1.3

AGRI COMMODITIES (\$/tonne)

Wheat	176.0	-4.1	300.0	0.1
Maize	181.9*	-9.3	298.0	-3.9
Sugar	334.6*	4.2	492.3	4.1
Palm oil	545.0	8.5	886.9	9.5
Rubber	1,372.6*	-35.4	1,738.7	-20.0
Coffee Robusta	1,213.0*	85.8	1,907.6	-16.5
Cotton	1,435.7	1.9	1,615.7	-11.3

As on Oct 24, 19 1800hrs IST, * Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:

1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LUFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price.

2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Nymex.

3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket.

4) International Natural Gas is LiffE near month future price & domestic natural Gas is MXX near month futures.

5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LUFFE future prices of near month contract.

6) International Maize is MALIF near month future, Rubber is Tokyo-1000M near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price.

7) Domestic Wheat & Rubber are NDXEF near month future price near month contract.

8) Domestic Coffee is Karnataka Robusta and Sugar is M30/Mumbai local spot price.

9) International cotton is COT 1002.

10) 2-INBOT near month future & domestic cotton is MXX future prices near month futures.

Bloomberg chartMaker

Compiled by BS Research Bureau

* As on Oct 24, 191800 hrs IST, * Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes: 1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future and Domestic natural gas is MXX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LFFE & Future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-100M near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no. 2-NYBOT near month future & domestic cotton is MXX future prices near month futures.

Bloomberg chartMaker Compiled by BS Research Bureau

हमारे कॉटन फाइबर प्रोडक्ट्स का अब किया गया है विस्तार!

कपास कॉन्ट्रैक्ट अब व्यापार के लिए उपलब्ध

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें

www.mcxindia.com

Name Exchange (Units)				
Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (युच्वार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Oct 31	19470, 19540, 19440, 19510.....	1284	224	2185
Nov 29	19260, 19340, 19240, 19320.....	961	171	7725
Dec 31	19250, 19340, 19230, 19310.....	187	38	3601
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2202, 2264, 2185, 2260.....	44860	2655	50700
Jan 20	2128, 2175, 2115, 2171.5.....	6340	454	22730
Feb 20	2132, 2175, 2132, 2161.5.....	1760	91	4930
Mar 20	2160, 2194, 2160, 2192.....	180	10	5000
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1082.5, 1090.5, 1081, 1089.....	604	142	336
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1084, 1091, 1080.5, 1089.....	672	455	3650
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Nov 20	2090, 2090, 2090, 2090.....	10	1	90
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Nov 20	3990, 4032, 3978, 4024.....	38880	2806	64150
Dec 20	4042, 4080, 4027.5, 4071.5.....	6340	926	19280
Jan 20	4574, 4580, 4538, 4576.....	1905	25	6485
Feb 20	4005, 4240, 4005, 4210.....	1000	4	
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Nov 20	4472, 4494, 4402, 4456.....	4380	447	61270
Dec 20	4550, 4556, 4460, 4526.....	1905	187	19440
Jan 20	4574, 4580, 4538, 4576.....	1905	25	6485
Feb 20	4490, 4598, 4490, 4560.....	1110	27	450
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Oct 31	562.9, 569.9, 560.5, 569.2.....	9400	502	14930
Nov 29	568.3, 578.8, 566.9, 576.5.....	19840	1231	49630
Dec 31	571.1, 580.8, 569, 578.4.....	2700	169	11060
Jan 31	563, 574.6, 563, 570.3.....	260	23	2080
Mentha Oil MCX(1 K)				
Oct 31	1211.9, 1213.3, 1194, 1197.....	358.56	837	157.32
Nov 29	1222.9, 1227.8, 1210.5, 1212.2.....	396.36	965	331.56
Dec 31	1231.8, 1239, 1231.8, 1235.3.....	1.08	3	1.8

उपहार में सोने का सिक्का चित

कंपनियों का राख गिफ्ट वाउचर की ओर, सोने की गिन्नी की मांग में गिरावट

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 24 अक्टूबर

इस साल सोना 20 फीसदी महंगा होने की वजह से भारतीय कंपनियों ने धनतेरस और दीवाली पर अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए सरफा या आभूषण खरीद की खातिर वाउचरों का सहारा लिया है। इस साल धनतेरस और दीवाली 25 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को पड़ रही है।

कई कंपनियां ने वाउचर खरीदने के लिए बड़े स्तर पर ऑर्डर दिए हैं जो उन्हें वास्तविक मुद्रित मूल्य से 10-15 प्रतिशत कम पर मिलते हैं। पिछले सालों के दौरान ये कंपनियां उपहार में देने के लिए मुख्य रूप से 5, 10 और 20 ग्राम मूल्यवान् वाले सोने के सिक्के खरीदा करते थे जो उनके कारोबार में भागीदारों द्वारा दिए गए योगदान पर निभर रहता था।

कल्याण ज्वैलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याणरम्पण ने कहा कि कल्याण ज्वैलर्स के पास ऑर्डर का आकार सोने से वाउचर में तब्दील हो गया है जिसे भुनाना बहुत आसान होता है। वाउचर से ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पसंद का सरफा या आभूषण खरीदने की छूट मिल जाती है। इस साल हमें कॉरपोरेट वाउचर की बिक्री में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा नजर आया है।



फिलहाल 38,296 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चलने वाले स्टैंडर्ड सोने के दामों में पिछले एक साल के दौरान 20.4 प्रतिशत तक की उछाल आ चुकी है, जबकि पिछली दीवाली के दौरान दाम 31,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थे। चांदी का भाव भी 19.2 प्रतिशत तक उछलकर आज 45,560 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुका है, जबकि एक साल पहले यह भाव 38,230 रुपये प्रति किलोग्राम था।

देश के सबसे बड़े ग्रैंडेड खुदरा आभूषण विक्रेताओं में शुमार तनिक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा और विपणन) संदीप कुलहल्ली ने कहा कि सोने का सिक्का धनतेरस और दीवाली के अवसर पर पोर्टफोलियो उपभोक्ताओं की खरीद का एक हिस्सा रहता है। सोने के सिक्के केवल धनतेरस के लिए ही नहीं खरीदे जाते, बल्कि

योजनाओं और छूट समेत अन्य संबंधित प्रोत्साहनों की वजह से भी उपभोक्ता अन्य अवसरों पर भी सोना खरीदते रहते हैं। हालांकि इस सीजन में सोने के सिक्कों में अच्छा इजाफा नहीं दिख रहा है लेकिन यह गिरावट का संकेत भी नहीं दे रहा है। त्योहार के इस दौर में सोने के सिक्कों की तुलना में स्वर्ण आभूषणों में अच्छा इजाफा देखा जा रहा है। जुलाई-अगस्त के दौरान सोने की अधिक कीमतों के कारण आभूषणों की खरीद की धारणा कुछ नकारात्मक थी लेकिन ऐसा लगता है कि उपभोक्ताओं ने सरफा का यह अधिक मूल्य स्तर स्वीकार कर लिया है। उपभोक्ताओं ने दुकानों पर वापस आना शुरू कर दिया है। कल्याण ज्वैलर्स का अनुमान है कि धनतेरस और दीवाली को मिलाकर त्योहारों के इस दौर में कुल बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी और इस अवसर पर उनके पास हल्के

आई गिरावट

■ एक साल के दौरान सराफा के दामों में आई 20 प्रतिशत की तेजी

■ पिछले कुछ दिनों के दौरान उपभोक्ताओं की खरीदारी की धारणा बढ़ी

■ शादी-विवाह और सोने के हल्के गहनों की मांग ने जोर पकड़ा

वजन वाले आभूषणों के बड़े ऑर्डरों की बुकिंग है। कुलहल्ली ने कहा कि पिछले पांच दिनों के दौरान सोने के आभूषणों की त्योहारी बिक्री में बढ़ी उछाल आई है। कुल मिलाकर हमारा अनुमान है कि इस साल सोने और हीरे के आभूषणों की बिक्री में असाधारण वृद्धि होगी।

इस बीच जौहरियों को इस सीजन में उपभोक्ताओं का झुकाव हीरे के आभूषणों के प्रति भी होता दिख रहा है। पिछले एक साल के दौरान हीरे के दामों में स्थिरता और जौहरियों द्वारा भारी छूट दिए जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। मिसाल के तौर पर तनिक हीरे के आभूषणों के दामों में 25 प्रतिशत की छूट और सोने के आभूषणों की बनाई पर भी कई तरह की छूट दे रही है। कल्याण और अन्य जौहरी भी एक सीमा से अधिक आभूषणों की खरीद पर भारी छूट और मुफ्त पेशकश कर रहे हैं।

एमसीएक्स			एनसीडीईएक्स			एमसीएक्स बढ़ा/घटा			एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा			एमसीएक्स बढ़त/छूट			एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट		
Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)	Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)	Name (Maturity)	Close	Day*	Name (Maturity)	Close	Day*	Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis	Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Agri commodity			Agri commodity			Gainers (* % Change)			Gainers (* % Change)			Premium over spot price (In %)			Premium over spot price (In %)		
Cotton	31.0	14013	Cotton	132.6	82510	Cardamom (Nov 15)	2537.8	3.5	CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2260.0	2.8	Cotton-Rajkot (Oct 31)	19510.0	2.6	Paddy-Basmati-Karnal (Nov 20)	3593.0	5.7
Oil and Oilseeds	276.0	78191				Crude Oil Mumbai (Nov 19)	3947.0	2.5	Coriander-Kota (Nov 20)	6490.0	2.2	Discount over spot price (In %)			Soy Bean-Akola (Nov 20)	3762.0	0.9
Spices	1.8	17	Grains	206.7	88400	Crude Oil (Nov 19)	3948.0	2.5	GuarGum 57-Jodhpur (Nov 20)	7550.0	1.7	Menthhol Oil Chandausa (Oct 31)	1197.0	-11.7	Moong-Merta City (Nov 20)	6451.0	0.7
Metal(Oct 23)						Crude Palm Oil (Oct 31)	569.2	1.1	Soyabene Indore (Nov 20)	3784.0	1.2	Aluminium Mum (Oct 31)	131.3	-5.5	Discount over spot price (In %)		
			Oil and Oilseeds	598.2	360335	Zinc Oct(31)	185.7	0.6	Guar Seed 10 (Nov 20)	4024.0	1.1	Alumini-Mumbai (Oct 31)	131.4	-5.5	Maize-Sangli (Nov 20)	1990.0	-17.1
Metal- non ferrous	5850.3	82661				Zinc Mini Oct(31)	185.7	0.6	Ref Soy Oil-DR-2016 (Nov 20)	761.4	0.6	Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	-5.4	Coriander-Kota (Nov 20)	6490.0	-2.3
Metal- precious	7931.0	423	Others	153.2	64425	Natural Gas (Oct 25)	162.2	0.6	Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1089.0	0.6	Lead Mini Mumbai (Oct 31)	156.1	-4.8	Turmeric Nizamabad (Nov 20)	5996.0	-2.1
						Lead Oct(31)	156.1	0.4	Losers <=5* (% Change)			Lead Mum (Oct 31)	156.1	-4.8	Jeera Unjha (Nov 20)	16290.0	-1.0
Oil and gas(Oct 23)			Pulses	184.8	77035	Kapas (Apr 30)	1089.0	0.4	Turmeric Nizamabad (Nov 20)	5996.0	-2.0	Zinc Mini Mumbai (Oct 31)	185.7	-3.6	Soy Bean Indore (Nov 20)	3784.0	-1.0
Gas	2034.6	31894				Losers (* % Change)			Wheat-Kota (Nov 20)	2131.0	-1.8	Zinc Mumbai (Oct 31)	185.7	-3.5	Crude Palm Oil Kandl (Oct 31)	567.0	-0.8
Oil	13433.8	1847	Spices	130.6	35431	Mentha Oil (Oct 31)	1197.0	-1.2	Jeera Unjha (Nov 20)	16290.0	-0.9	Nickel Mumbai (Oct 31)	1193.6	-2.8	Guar Gum 5 MT-Jodhpur (Nov 20)	7550.0	-0.6
						Nickel (Oct 31)	1193.6	-0.4	CastorSeed New-Disa (Nov 20)	4456.0	-0.7	Cardamom Vandamedu (Nov 15)	2537.8	-1.3	Barley Jaipur (Nov 20)	2090.0	-0.4
						Aluminium Oct 31)	131.3	-0.2	Chana-Bikaner (Nov 20)	4454.0	-0.3	Gold Ahm Dec (05)	38003.0	-0.7			

कल का हाजिर भाव																
औद्योगिक																
Metals																
Aluminium utensil scrap kg																
Aluminium ingots kg																
Brass sheet scrap/kg																
Copper heavy scrap/kg																
Copper utensil scrap/kg																
Copper wire bar/kg																
Lead ingots kg																
Nickel Cathodes/kg																
Tin slabs/kg																
Zinc slabs/kg																
Source: Bombay Metal Exchange																
Cotton																
Bengal Deshi (Q1)																
Bengal Deshi (Q2)																
Bengal Deshi (Q3)																
Bengal Deshi (Q4)																
Bengal Deshi (Q5)																
Bengal Deshi (Q6)																
Bengal Deshi (Q7)																
Bengal Deshi (Q8)																
Bengal Deshi (Q9)																
Bengal Deshi (Q10)																
Bengal Deshi (Q11)																
Bengal Deshi (Q12)																
Bengal Deshi (Q13)																
Bengal Deshi (Q14)																
Bengal Deshi (Q15)																
Bengal Deshi (Q16)																
Bengal Deshi (Q17)																
Bengal Deshi (Q18)																
Bengal Deshi (Q19)																
Bengal Deshi (Q20)																
Bengal Deshi (Q21)																
Bengal Deshi (Q22)																
Bengal Deshi (Q23)																
Bengal Deshi (Q24)																
Bengal Deshi (Q25)																
Bengal Deshi (Q26)																
Bengal Deshi (Q27)																
Bengal Deshi (Q28)																
Bengal Deshi (Q29)																
Bengal Deshi (Q30)																
Bengal Deshi (Q31)																
Bengal Deshi (Q32)																
Bengal Deshi (Q33)																
Bengal Deshi (Q34)																
Bengal Deshi (Q35)																
Bengal Deshi (Q36)																
Bengal Deshi (Q37)																
Bengal Deshi (Q38)																
Bengal Deshi (Q39)																
Bengal Deshi (Q40)																
Bengal Deshi (Q41)																
Bengal Deshi (Q42)																
Bengal Deshi (Q43)																
Bengal Deshi (Q44)																
Bengal Deshi (Q45)																
Bengal Deshi (Q46)																
Bengal Deshi (Q47)																
Bengal Deshi (Q48)																
Bengal Deshi (Q49)																
Bengal Deshi (Q50)																
Bengal Deshi (Q51)																
Bengal Deshi (Q52)																
Bengal Deshi (Q53)																
Bengal Deshi (Q54)																
Bengal Deshi (Q55)																
Bengal Deshi (Q56)																
Bengal Deshi (Q57)																
Bengal Deshi (Q58)																
Bengal Deshi (Q59)																
Bengal Deshi (Q60)																
Bengal Deshi (Q61)																
Bengal Deshi (Q62)																
Bengal Deshi (Q63)																
Bengal Deshi (Q64)																
Bengal Deshi (Q65)																
Bengal Deshi (Q66)																
Bengal Deshi (Q67)																
Bengal Deshi (Q68)																
Bengal Deshi (Q69)																
Bengal Deshi (Q70)																
Bengal Deshi (Q71)																
Bengal Deshi (Q72)																
Bengal Deshi (Q73)																
Bengal Deshi (Q74)																
Bengal Deshi (Q75)																
Bengal Deshi (Q76)																
Bengal Deshi (Q77)																
Bengal Deshi (Q78)																
Bengal Deshi (Q79)																
Bengal Deshi (Q80)																
Bengal Deshi (Q81)																
Bengal Deshi (Q82)																
Bengal Deshi (Q83)																
Bengal Deshi (Q84)																
Bengal Deshi (Q85)																
Bengal Deshi (Q86)																
Bengal Deshi (Q87)																
Bengal Deshi (Q88)																
Bengal Deshi (Q89)																
Bengal Deshi (Q90)																
Bengal Deshi (Q91)																
Bengal Deshi (Q92)																
Bengal Deshi (Q93)																
Bengal Deshi (Q94)																
Bengal Deshi (Q95)																
Bengal Deshi (Q96)																
Bengal Deshi (Q97)																
Bengal Deshi (Q98)																
Bengal Deshi (Q99)																
Bengal Deshi (Q100)																
Bengal Deshi (Q101)																
Bengal Deshi (Q102)																
Bengal Deshi (Q103)																
Bengal Deshi (Q104)																
Bengal Deshi (Q105)																
Bengal Deshi (Q106)																
Bengal Deshi (Q107)																
Bengal Deshi (Q108)																
Bengal Deshi (Q109)																
Bengal Deshi (Q110)																
Bengal Deshi (Q111)																
Bengal Deshi (Q112)																
Bengal Deshi (Q113)																
Bengal Deshi (Q114)																
Bengal Deshi (Q115)																
Bengal Deshi (Q116)																
Bengal Deshi (Q117)																
Bengal Deshi (Q118)																
Bengal Deshi (Q119)																
Bengal Deshi (Q120)																
Bengal Deshi (Q121)																
Bengal Deshi (Q122)																
Bengal Deshi (Q123)																
Bengal Deshi (Q124)																
Bengal Deshi (Q125)																
Bengal Deshi (Q126)																
Bengal Deshi (Q127)																
Bengal Deshi (Q128)																
Bengal Deshi (Q129)																
Bengal Deshi (Q130)																
Bengal Deshi (Q131)																
Bengal Deshi (Q132)																
Bengal Deshi (Q133)																
Bengal Deshi (Q134)																
Bengal Deshi (Q135)																
Bengal Deshi (Q136)																
Bengal Deshi (Q137)																
Bengal Deshi (Q138)																
Bengal Deshi (Q139)																
Bengal Deshi (Q140)																
Bengal Deshi (Q141)																
Bengal Deshi (Q142)																
Bengal Deshi (Q143)																
Bengal Deshi (Q144)																
Bengal Deshi (Q145)																
Bengal Deshi (Q146)																
Bengal Deshi (Q147)																
Bengal Deshi (Q148)																
Bengal Deshi (Q149)																
Bengal Deshi (Q150)																
Bengal Deshi (Q151)																
Bengal Deshi (Q152)																
Bengal Deshi (Q153)																
Bengal Deshi (Q154)																
Bengal Deshi (Q155)																
Bengal Deshi (Q156)																
Bengal Deshi (Q157)																
Bengal Deshi (Q158)																
Bengal Deshi (Q159)																
Bengal Deshi (Q160)																
Bengal Deshi (Q161)																
Bengal Deshi (Q162)																
Bengal Deshi (Q163)																
Bengal Deshi (Q164)																
Bengal Deshi (Q165)																
Bengal Deshi (Q166)																
Bengal Deshi (Q167)																
Bengal Deshi (Q168)																
Bengal Deshi (Q169)																
Bengal Deshi (Q170)																
Bengal Deshi (Q171)																
Bengal Deshi (Q172)																
Bengal Deshi (Q173)																
Bengal Deshi (Q174)																
Bengal Deshi (Q175)																
Bengal Deshi (Q176)																
Bengal Deshi (Q177)																
Bengal Deshi (Q178)																
Bengal Deshi (Q179)																
Bengal Deshi (Q180)																
Bengal Deshi (Q181)																
Bengal Deshi (Q182)																
Bengal Deshi (Q183)																
Bengal Deshi (Q184)																
Bengal Deshi (Q185)																
Bengal Deshi (Q186)																
Bengal Deshi (Q187)																
Bengal Deshi (Q188)																
Bengal Deshi (Q189)																
Bengal Deshi (Q190)																
Bengal Deshi (Q191)																
Bengal Deshi (Q192)																
Bengal Deshi (Q193)																
Bengal Deshi (Q194)																
Bengal Deshi (Q195)																
Bengal Deshi (Q196)																
Bengal Deshi (Q197)																
Bengal Deshi (Q198)																
Bengal Deshi (Q199)																
Bengal Deshi (Q200)																
Bengal Deshi (Q201)																
Bengal Deshi (Q202)																
Bengal Deshi (Q203)																
Bengal Deshi (Q204)																
Bengal Deshi (Q205)																
Bengal Deshi (Q206)																
Bengal Deshi (Q207)																
Bengal Deshi (Q208)																
Bengal Deshi (Q209)																
Bengal Deshi (Q210)																
Bengal Deshi (Q211)																
Bengal Deshi (Q212)																
Bengal Deshi (Q213)																
Bengal Deshi (Q214)																
Bengal Deshi (Q215)																
Bengal Deshi (Q216)																
Bengal Deshi (Q217)																
Bengal Deshi (Q218)																
Bengal Deshi (Q219)																
Bengal Deshi (Q220)																
Bengal Deshi (Q221)																
Bengal Deshi (Q222)																
Bengal Deshi (Q223)																
Bengal Deshi (Q224)																
Bengal Deshi (Q225)																
Bengal Deshi (Q226)																
Bengal Deshi (Q227)																
Bengal Deshi (Q228)																
Bengal Deshi (Q229)																
Bengal Deshi (Q230)																
Bengal Deshi (Q231)																
Bengal Deshi (Q232)																
Bengal Deshi (Q233)																
Bengal Deshi (Q234)																
Bengal Deshi (Q235)																
Bengal Deshi (Q236)																
Bengal Deshi (Q237)																
Bengal Deshi (Q238)																
Bengal Deshi (Q239)																
Bengal Deshi (Q240)																
Bengal Deshi (Q241)																
Bengal Deshi (Q242)																
Bengal Deshi (Q243)																
Bengal Deshi (Q244)																
Bengal Deshi (Q245)																
Bengal Deshi (Q246)																
Bengal Deshi (Q247)																
Bengal Deshi (Q248)																
Bengal Deshi (Q249)																
Bengal Deshi (Q250)																
Bengal Deshi (Q251)																
Bengal Deshi (Q252)																
Bengal Deshi (Q253)																
Bengal Deshi (Q254)																
Bengal Deshi (Q255)																
Bengal Deshi (Q256)																
Bengal Deshi (Q257)																
Bengal Deshi (Q258)																
Bengal Deshi (Q259)																
Bengal Deshi (Q260)																
Bengal Deshi (Q261)																
Bengal Deshi (Q262)																
Bengal Deshi (Q263)																
Bengal Deshi (Q264)																
Bengal Deshi (Q265)																
Bengal Deshi (Q266)																
Bengal Deshi (Q267)																
Bengal Deshi (Q268)																
Bengal Deshi (Q269)																
Bengal Deshi (Q270)																
Bengal Deshi (Q271)																
Bengal Deshi (Q272)																
Bengal Deshi (Q273)																
Bengal Deshi (Q274)																
Bengal Deshi (Q275)																
Bengal Deshi (Q276)																
Bengal Deshi (Q277)																
Bengal Deshi (Q278)																
Bengal Deshi (Q279)																
Bengal Deshi (Q280)																
Bengal Deshi (Q281)																
Bengal Deshi (Q282)																
Bengal Deshi (Q283)																
Bengal Deshi (Q284)																
Bengal Deshi (Q285)																
Bengal Deshi (Q286)																
Bengal Deshi (Q287)																
Bengal Deshi (Q288)																
Bengal Deshi (Q289)																
Bengal Deshi (Q290)																
Bengal Deshi (Q291)																
Bengal Deshi (Q292)																
Bengal Deshi (Q293)																
Bengal Deshi (Q294)																
Bengal Deshi (Q295)																
Bengal Deshi (Q296)																
Bengal Deshi (Q297)																
Bengal Deshi (Q298)																
Bengal Deshi (Q299)																
Bengal Deshi (Q300)																
Bengal Deshi (Q301)																
Bengal Deshi (Q302)																
Bengal Deshi (Q303)																
Bengal Deshi (Q304)																
Bengal Deshi (Q305)																
Bengal Deshi (Q306)																
Bengal Deshi (Q307)																
Bengal Deshi (Q308)																
Bengal Deshi (Q309)																
Bengal Deshi (Q310)																
Bengal Deshi (Q311)																
Bengal Deshi (Q312)																
Bengal Deshi (Q313)																
Bengal Deshi (Q314)																
Bengal Deshi (Q315)																
Bengal Deshi (Q316)																
Bengal Deshi (Q317)																
Bengal Deshi (Q318)																
Bengal Deshi (Q319)																
Bengal Deshi (Q320)																
Bengal Deshi (Q321)																
Bengal Deshi (Q322)																
Bengal Deshi (Q323)																
Bengal Deshi (Q324)																
Bengal Deshi (Q325)																
Bengal Deshi (Q326)																
Bengal Deshi (Q327)																
Bengal Deshi (Q328)																
Bengal Deshi (Q329)																
Bengal Deshi (Q330)																
Bengal Deshi (Q331)																
Bengal Deshi (Q332)																
Bengal Deshi (Q333)																
Bengal Deshi (Q334)																
Bengal Deshi (Q335)																
Bengal Deshi (Q336)																
Bengal Deshi (Q337)																
Bengal Deshi (Q338)																
Bengal Deshi (Q339)																
Bengal Deshi (Q340)																
Bengal Deshi (Q341)																
Bengal Deshi (Q342)																
Bengal Deshi (Q343)																
Bengal Deshi (Q344)																
Bengal Deshi (Q345)																
Bengal Deshi (Q346)																
Bengal Deshi (Q347)																
Bengal Deshi (Q348)																
Bengal Deshi (Q349)																
Bengal Deshi (Q350)																
Bengal Deshi (Q351)																
Bengal Deshi (Q352)																
Bengal Deshi (Q353)																
Bengal Deshi (Q354)																
Bengal Deshi (Q355)																
Bengal Deshi (Q356)																
Bengal Deshi (Q357)																
Bengal Deshi (Q358)																
Bengal Deshi (Q359)																
Bengal Deshi (Q360)																
Bengal Deshi (Q361)																
Bengal Deshi (Q362)																
Bengal Deshi (Q363)																
Bengal Deshi (Q364)																
Bengal Deshi (Q365)																
Bengal Deshi (Q366)																
Bengal Deshi (Q367)																
Bengal Deshi (Q368)																
Bengal Deshi (Q369)																
Bengal Deshi (Q370)																
Bengal Deshi (Q371)																
Bengal Deshi (Q372)																
Bengal Deshi (Q373)																
Bengal Deshi (Q374)																
Bengal Deshi (Q375)																
Bengal Deshi (Q376)																
Bengal Deshi (Q377)																
Bengal Deshi (Q378)																
Bengal Deshi (Q379)																
Bengal Deshi (Q380)																
Bengal Deshi (Q381)																
Bengal Deshi (Q382)																
Bengal Deshi (Q383)																
Bengal Deshi (Q384)																
Bengal Deshi (Q385)																
Bengal Deshi (Q386)																
Bengal Deshi (Q387)																
Bengal Deshi (Q388)																
Bengal Deshi (Q389)																
Bengal Deshi (Q390)																
Bengal Deshi (Q391)																
Bengal Deshi (Q392)																
Bengal Deshi (Q393)																
Bengal Deshi (Q394)																
Bengal Deshi (Q395)																
Bengal Deshi (Q396)																
Bengal Deshi (Q397)																
Bengal Deshi (Q398)																
Bengal Deshi (Q399)																
Bengal Deshi (Q400)																
Bengal Deshi (Q401)																
Bengal Deshi (Q402)																
Bengal Deshi (Q403)																
Bengal Deshi (Q404)																
Bengal Deshi (Q405)																
Bengal Deshi (Q406)																
Bengal Deshi (Q407)																
Bengal Deshi (Q408)																
Bengal Deshi (Q409)																
Bengal Deshi (Q410)																
Bengal Deshi (Q411)																
Bengal Deshi (Q412)																
Bengal Deshi (Q413)																
Bengal Deshi (Q414)																
Bengal Deshi (Q415)																
Bengal Deshi (Q416)																
Bengal Deshi (Q417)																
Bengal Deshi (Q418)																
Bengal Deshi (Q419)																
Bengal Deshi (Q420)																
Bengal Deshi (Q421)																
Bengal Deshi (Q422)																
Bengal Deshi (Q423)																
Bengal Deshi (Q424)																
Bengal Deshi (Q425)																
Bengal Deshi (Q426)																
Bengal Deshi (Q427)																
Bengal Deshi (Q428)																
Bengal Deshi (Q429)																
Bengal Deshi (Q430)																
Bengal Deshi (Q431)																
Bengal Deshi (Q432)																
Bengal Deshi (Q433)																
Bengal Deshi (Q434)																
Bengal Deshi (Q435)																
Bengal Deshi (Q436)																
Bengal Deshi (Q437)																
Bengal Deshi (Q438)																
Bengal Deshi (Q439)																
Bengal Deshi (Q440)																
Bengal Deshi (Q441)																
Bengal Deshi (Q442)																
Bengal Deshi (Q443)																
Bengal Deshi (Q444)																
Bengal Deshi (Q445)																
Bengal Deshi (Q446)																
Bengal Deshi (Q447)																
Bengal Deshi (Q448)																
Bengal Deshi (Q449)																
Bengal Deshi (Q450)																
Bengal Deshi (Q451)																
Bengal Deshi (Q452)																
Bengal Deshi (Q453)																
Bengal Deshi (Q454)																
Bengal Deshi (Q455)																
Bengal Deshi (Q456)																
Bengal Deshi (Q457)																
Bengal Deshi (Q458)																
Bengal Deshi (Q459)																
Bengal Deshi (Q460)																
Bengal Deshi (Q461)																
Bengal Deshi (Q462)																
Bengal Deshi (Q463)																
Bengal Deshi (Q464)																
Bengal Deshi (Q465)																
Bengal Deshi (Q466)																
Bengal Deshi (Q467)																
Bengal Deshi (Q468)																
Bengal Deshi (Q469)																
Bengal Deshi (Q470)																
Bengal Deshi (Q471)																
Bengal Deshi (Q472)																
Bengal Deshi (Q473)																
Bengal Deshi (Q474)																
Bengal Deshi (Q475)																
Bengal Deshi (Q476)																
Bengal Deshi (Q477)																
Bengal Deshi (Q478)																
Bengal Deshi (Q479)																
Bengal Deshi (Q480)																
Bengal Deshi (Q481)																
Bengal Deshi (Q482)																
Bengal Deshi (Q483)																
Bengal Deshi (Q484)																
Bengal Deshi (Q485)																
Bengal Deshi (Q486)																
Bengal Deshi (Q487)																
Bengal Deshi (Q488)																
Bengal Deshi (Q489)																
Bengal Deshi (Q490)																
Bengal Deshi (Q491)																
Bengal Deshi (Q492)																
Bengal Deshi (Q493)																
Bengal Deshi (Q494)																
Bengal Deshi (Q495)																
Bengal Deshi (Q496)																
Bengal Deshi (Q497)																
Bengal Deshi (Q498)																
Bengal Deshi (Q499)																
Bengal Deshi (Q500)																
Bengal Deshi (Q501)																
Bengal Deshi (Q502)																
Bengal Deshi (Q503)																
Bengal Deshi (Q504)																
Bengal Deshi (Q505)																
Bengal Deshi (Q506)																
Bengal Deshi (Q507)																
Bengal Deshi (Q508)																
Bengal Deshi (Q509)																
Bengal Deshi (Q510)																
Bengal Deshi (Q511)																
Bengal Deshi (Q512)																
Bengal Deshi (Q513)																
Bengal Deshi (Q514)																
Bengal Deshi (Q515)																
Bengal Deshi (Q516)																
Bengal Deshi (Q517)																
Bengal Deshi (Q518)																
Bengal Deshi (Q519)																
Bengal Deshi (Q520)																
Bengal Deshi (Q521)																
Bengal Deshi (Q522)																
Bengal Deshi (Q523)																
Bengal Deshi (Q524)																
Bengal Deshi (Q525)																
Bengal Deshi (Q526)																
Bengal Deshi (Q527)																
Bengal Deshi (Q528)																
Bengal Deshi (Q529)																
Bengal Deshi (Q530)																
Bengal Deshi (Q531)																
Bengal																

महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन, हरियाणा में अड़चन

महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को मिला पूर्ण बहुमत लेकिन हरियाणा में रह गई कसर



मुंबई में भाजपा को भारी जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

फोटो: पीटीआई



हरियाणा में भाजपा समर्थक जीत का जश्न मनाते हुए

फोटो: पीटीआई

चुनावी नतीजों ने दिखाए मंदी के मायने

संजीव मुखर्जी और
अरूण रायचौधरी

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन संतोषजनक स्तर से कमजोर रहा है। इससे फिर यह सवाल उठा है कि वह अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की आवाज उठने लगी है। ऐसा लग रहा है कि दोनों राज्यों में बहुत सी सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र की निर्णायक भूमिका रही है।

इन चुनावी नतीजों ने यह भी संकेत दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग, मजदूरी और खपत में लगातार मंदी ने राजनीतिक जमीं पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा बहुत से थोड़े पीछे रह गई है, जबकि इसने 2019 के आम चुनावों में मोदी लहर की बदौलत राज्य की सभी 10 लोक सभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा-शिव सेना की सीटों की संख्या 2014 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले 27 कम हो गई है।

सत्तारूढ़ पार्टी के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े अन्य संगठनों ने स्वीकार किया है कि मतदाताओं ने आर्थिक मुद्दों विशेष रूप से नौकरियों और ग्रामीण संकट से निपटने के सरकार के तरीकों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि भाजपा के संतोषजनक स्तर से



भाजपा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दे सकती है ज्यादा जोर

कमजोर प्रदर्शन में स्थानीय मुद्दों, राज्य नेतृत्व से असंतोष, जाति और सांप्रदायिक कारकों की भूमिका रही है। लेकिन पार्टी के सूत्रों ने यह भी कहा कि आर्थिक मुद्दे भी जनता के जेहन में थे।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, 'हम निश्चित रूप से इन मुद्दों के बदलावों की अत्यधिक जरूरत है।' और सरकार के साथ चर्चा करेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जमीनी स्थितियों से निपटने के तरीकों में कुछ

भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने कहा, 'हम इसी बात से हैरान थे कि ग्रामीण खस्ताहाली का राजनीति पर असर क्यों नहीं दिख रहा है। संभवतया इसने असर दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि अगर आप उन क्षेत्रों को देखेंगे, जहां भाजपा ने जमीन

गंवाई है तो वे ग्रामीण इलाके हैं।' सेन ने कहा कि जब भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारी थी तो उनकी नीति की दिशा में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि हालांकि अब मंदी की चर्चा जोर पकड़ गई है।

उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि अब केंद्र ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा जोर देगा। आखिरकार लोग अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मत देते हैं। अब सरकार को उन योजनाओं को ठीक से लागू करने की जरूरत है, जिनकी वह पहले ही घोषणा कर चुकी है।' आधार से जोड़ने की अनिवार्यता जैसे प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों के कारण कई राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त अटकी हुई है।

भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव

चाहती है। विपक्ष भी इसमें अपनी संभावना टटोल रहा है। उसका कहना है कि शिव सेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलकर सरकार बनानी चाहिए। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह ने महाराष्ट्र में दिया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर अपने पद पर बरकरार रहेंगे। मोदी ने कहा कि इन दोनों नेताओं के पास अनुभव नहीं था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साफ सुथरी सरकार दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सहयोगी दलों को साथ

शिराज हुसैन ने कहा, 'मेरा मानना है कि इन दो विधानसभा चुनावों के नतीजों का स्पष्ट संदेश यह है कि महज भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए आर्थिक मुद्दों विशेष रूप से ग्रामीण आबादी से जुड़े मुद्दों का तत्काल समाधान निकालने की जरूरत है।'

हरियाणा मुख्य रूप से ग्रामीण राज्य है। यहां पिछले दो वर्ष से लगातार फसलों की कीमतें गिर रही हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह राज्य उन राज्यों में से एक है, जहां सबसे अधिक बेरोजगारी है। महाराष्ट्र भी औद्योगिक राज्य है। सूत्रों का कहना है कि इस बात के आसार हैं कि राज्य में कुछ सीटों पर मंदी ने अहम भूमिका अदा की हो। अप्रैल-जून तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 5 फीसदी था, जो 2013 के बाद सबसे कम है। नॉमिनल जीडीपी की दर घटकर 8 फीसदी पर आ गई, जो वर्ष 2002-03 की तीसरी तिमाही के बाद सबसे कम है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्षेत्रों में मंदी के कारण कई उपायों की घोषणा की थी। इसमें से एक कॉरपोरेट कर की दर में कमी करना था। यह कदम पूंजी उपलब्धता और निवेश बढ़ाने की उम्मीद में उठाया गया था ताकि मजदूरी की दरों में भी इजाफा हो। हालांकि ये सब आपूर्ति पक्ष से संबंधित उपाय थे और मांग पक्ष से संबंधित कोई उपाय नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग अब भी कमजोर बनी हुई है।

लेने में विश्वास करती है। यह इस बात का संकेत है कि भाजपा और शिवसेना के बीच समझौता होगा।

इन चुनावी नतीजों ने शरद पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे क्षेत्रीय नेताओं को भी संजीवनी देने का काम किया है। पवार की राकांपा ने महाराष्ट्र में अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 54 सीटें जीती जबकि हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को 31 सीटें जिताने में सफल रहे। हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं के साथ तकरार के बावजूद यह सफलता हासिल की।

प्रत्याशी जो हारे एवं जीते



पंकजा मुंडे
भाजपा
पल्ली सीट से हारी



रणदीप सिंह सुरजेवाला
कांग्रेस
कैथल सीट से हारे



कैप्टन अभिमन्यु
भाजपा
नारखैद से हारे



सुभाष बराला
भाजपा
देहना सीट से हारे



दुष्यंत चौटाला
जननायक जनता पार्टी
उचनला कलां

हरियाणा में बन सकती है भाजपा सरकार

नितिन कुमार और अर्चिस मोहन

गुरुवार को घोषित हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में 12 हालिया मंत्रियों में से केवल तीन ही अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और इस शर्मिंदगी के बीच भारतीय जनता पार्टी प्रमुख अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया। हालांकि हरियाणा में भाजपा के अधिकांश मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए लेकिन यह राज्य में सबसे अधिक सीट जीतने वाला दल बनकर उभरी है। साथ ही 2014 विधानसभा काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं कि भाजपा की कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर राज्य में दोबारा सरकार बना सकती है।

नौ मंत्रियों समेत भाजपा के राज्य प्रमुख सुभाष बराला की हार ने हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ बह रही हवा को स्पष्ट कर दिया है। चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के वोट प्रतिशत में भी भारी कमी आई है और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी

(जेजेपी) ने इसमें सेध लगाई है।

राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 90 में से 75 विधानसभा सीटें जीतने का नारा दिया था। वर्ष 2014 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई 'देंगे।' वर्ष 2014 में सुशासन के नाम पर राज्य में सरकार बनाने वाली भाजपा के खिलाफ अपने वादे पूरे नहीं करने को लेकर लोगों में गुस्सा था। चुनाव जीतने के लिए 35 जातियों को एक साथ लाने और जाटों को अलग-थलग करने की भाजपा की रणनीति सफल नहीं हो सकी। फरवरी 2016 के आंदोलन एवं सांप्रदायिक हिंसा के बाद जाट खट्टर सरकार से काफी नाराज थे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व

में कांग्रेस पार्टी ने दूसरे समुदायों, विशेषकर ब्राह्मण और दलितों के बीच अपनी पैठ बनाई। हुड्डा की मजबूत पकड़ वाले रोहतक, सोनीपत, पानीपत और जींद में कांग्रेस ने सीटें जीतीं। इसी तरह, जेजेपी के प्रत्याशियों ने सिरसा, भिवानी और हिसार में जीत दर्ज की जिन्हें चौटाला परिवार से प्रभावित क्षेत्र माना जाता था।

खट्टर सरकार को सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद जिले के रतीराम कहते हैं, 'हमारा बेटा चपरसी और गुजरात का बालक अफसर की नौकरी पा रहा है। क्या हमारा पढ़ा लिखा बालक चाय बेचेगा?' एक किसान ने कहा, 'ये खट्टर खुद चपरसी था तो हमारे बालक की भी चपरसी ही बनाएगा।' विपक्ष खट्टर सरकार की 'बिना खर्ची और पर्वी की सरकार' वाली छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एसडीओ भती में

चयनित कुल 80 में से 78 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से से जिसने हरियाणा के लोगों को निराशा किया। समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर राज्य के युवाओं तथा अधिकारी पदों के लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को चुनाव सरकार के लिए सही नहीं रहा। राज्य सरकार किसानों

की समस्या की भी बेहतर समाधान नहीं खोज सकी। प्रति एकड़ उत्पादन की सीमा, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, और समर्थन मूल्य की कमी से भाजपा को किसानों का समर्थन नहीं मिल सका। 19 वर्षों के बाद पहली बार राज्य में सबसे कम (65 प्रतिशत) मतदान हुआ। खट्टर के चुनाव क्षेत्र करनाल में केवल 50 प्रतिशत मतदान हुआ। हरियाणा में 28 प्रतिशत के साथ देश की सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। मारुति सुजुकी और दूसरी कंपनियों द्वारा उत्पादन में कटौती की खबरों ने भी विपक्ष को काफी मदद दी। हुड्डा ने अनुच्छेद 370 के समाप्त करने का समर्थन करके भाजपा के चुनावी अभियान को सुस्त कर दिया। खिलाड़ियों को टिकट देने की भाजपा की रणनीति भी ज्यादा सफल नहीं हो सकी और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त हिंसा के बाद जाट खट्टर सरकार से काफी नाराज थे।

सिंह ने अपनी सीट पर जीत दर्ज की।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने जीती हारी हुई बाजी

सातारा की रैली से स्थिति पलटी, जब 79 साल के बीमार पवार ने बारिश में भीगते हुए जन सभा को संबोधित किया तो हजारों कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गए

आदिति फडणीस

इस साल आम चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माहा लोक सभा क्षेत्र के सांसद विजयसिंह मोहिते पाटिल ने घोषणा की थी कि क्या उनके नेता- शरद पवार को लोक सभा चुनाव लड़ने का फैसला लेना चाहिए। अगर पवार ऐसा करते हैं तो वह दौड़ से हट जाएंगे और अपनी सीट उनके लिए छोड़ देंगे। पवार ने इस विचार पर सार्वजनिक रूप से विचार किया। लेकिन जब नामों की घोषणा की गई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोलापुर जिला परिषद के अध्यक्ष संजय शिंदे को उम्मीदवार के रूप में उतारा। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ने खुलासा किया, 'पवार ने हमारे साथ चर्चा की थी' और वह संभवतया यह सीट जीतने को लेकर आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला

किया। उन्होंने बताया कि कल्पना कीजिए कि एक जानी-मानी हस्ती और महाराष्ट्र में एक पुराने राजनेता के लोक सभा चुनाव हार जाने पर क्या होता।

संभव है कि पवार के लिए यही चेतने का वक्त था। उसके बाद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनने और उन्हें एकजुट करने में अथक मेहनत की। यह सब करना आसान नहीं रहा। चुनाव प्रचार के दौरान जब एक संवाददाता ने पवार से पूछा कि उनके 'जाति भाई' उन्हें छोड़ रहे हैं और राकांपा से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इस पर पवार आपा खो बैठे थे। पवार ने कहा, 'आप मेरे से केवल राजनीति के बारे में पूछ सकते हैं।' उन्हें संवाददाता से कहा, 'इसमें परिवार को क्यों घसीट रहे हैं? आपमें संवाददाता के गुण नहीं हैं।' लेकिन असल तथ्य यह है कि इस सवाल

ने पवार को बहुत असहज कर दिया था। उस समय चुनावी अभियान चल रहा था और राकांपा के करीब एक दर्जन शीर्ष नेता भाजपा में जा चुके थे। इस घटनाक्रम ने पवार को मुकाबले के लिए और मजबूत किया। उन्होंने अपना हर



राकांपा प्रमुख शरद पवार

ने पवार को बहुत असहज कर दिया था। उस

समय चुनावी अभियान चल रहा था और राकांपा के करीब एक दर्जन शीर्ष नेता भाजपा में जा चुके थे। इस घटनाक्रम ने पवार को मुकाबले के लिए और मजबूत किया। उन्होंने अपना हर

क्षण चुनाव प्रचार या अपने सिपहसलारों के साथ रणनीति की चर्चा में इस्तेमाल किया। उनका एकमात्र ध्येय भाजपा-शिवसेना को हराना था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा था कि पवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे क्षेत्रीय नेताओं को भी संजीवनी देने का काम किया है। पवार की राकांपा ने महाराष्ट्र में अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 54 सीटें जीती जबकि हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस को 31 सीटें जिताने में सफल रहे। हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके करीबी नेताओं के साथ तकरार के बावजूद यह सफलता हासिल की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि वह पवार का सम्मान करते हैं। मोदी ने कुछ साल पहले एक जन

सभा में कहा था, 'मैं शरदराव का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था...तब उन्होंने मुझे राजनीति के गुरु सिखाए थे। मुझे सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है।' लेकिन राजनीति उस समय व्यक्तिगत हो गई, जब महाराष्ट्र चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवालिया पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से पवार का नाम जोड़ा था। इससे पवार का व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप से लड़ने का संकल्प और मजबूत हो गया।

हालांकि पवार के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन उनके सभी राजनीतिक दलों में प्रशंसक और समर्थक हैं। उनका सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके संबोधनों में भाषणों में नारेबाजी, भाषणबाजी नहीं होती है। वह ज्यादातर तथ्यों पर बात करते हैं और अपने काम पर बात करते हैं।

इसके अलावा शरद पवार के बिना राकांपा की कल्पना नहीं की जा सकती है।

अगर मोदी ने भाजपा के लिए चुनाव जीता है तो पवार ने राकांपा के लिए चुनाव जीता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सातारा की रैली से स्थितिवां बदल गई। जब 79 वर्षीय अस्वस्थ पवार जन सभा को संबोधित कर रहे तो भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने बारिश में भीगते हुए ही जनता को संबोधित किया। उन्होंने छाता लेने से भी इनकार कर दिया। यह देखकर पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, 'जब आप सभी बारिश से लड़ रहे हैं तो मैं कैसे छाते की आड़ ले सकता हूँ।' इसका नतीजा था कि जो लोग पवार को छोड़कर गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि पवार ने महाराष्ट्र के लोगों में दिलों में राकांपा के लिए फिर जगह बनाई है।

उपचुनाव: दल-बदलुओं को शिकस्त

टी ई नरसिम्हन, दशरथ रेड्डी और अर्चिस मोहन

दो लोकसभा और 51 विधानसभा सीटों के परिणाम भाजपा के साथ साथ विपक्ष के लिए भी काफी हद तक मिश्रित रहे हैं। हालांकि जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वह यह कि कुछ दल-बदलुओं को इस उपचुनाव में शिकस्त खानी पड़ी है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने महाराष्ट्र में सतारा लोकसभा सीट बरकरार रखी है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर सीट को बचाने में सफल रही। राकांपा के श्रीनिवास पाटिल ने सतारा में भाजपा के उदयनराजे भोसले को मात दी। मराठा राजा शिवाजी के वंशज भोसले ने पिछले महीने राकांपा का दामन छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें अपनी लोकसभा सीट खाली करनी पड़ी थी। सतारा में चुनाव प्रचार के आखिर में 18 अक्टूबर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बारिश के बीच अपना भाषण दिया था, जिससे उनके प्रति सहानुभूति देखने को मिली थी। पाटिल ने कहा, ‘शरद पवार साहब ने उन्हें सतारा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। लेकिन भोसले ने पवार साहब को धोखा दिया और लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया।’

गुजरात

गुजरात में, 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस खबर लिखे जाने



चेन्नई में अन्नाद्रमुक समर्थक उपचुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए फोटो: पीटीआई

तक तीन-तीन सीटों पर आगे चल रही थीं। भाजपा के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर को राधनपुर सीट से हार मिली। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जीती थी। उनके करीबी धवलसिंह झाला भी को भी बायडू विधानसभा सीट से हाथ धोना पड़ा है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक को दोनों सीटों पर जीत मिली। इन सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव हुआ था। वहीं पुदुच्चेरी में हुए चुनाव में कांग्रेस एक सीट झोली में डालने में कामयाब रही। अन्नाद्रमुक उम्मीदवारों ने विक्रावंडी और नंगुनेरी विधानसभा सीटें भारी अंतर से जीतीं, जबकि कांग्रेस को पुडुचेरी में

कामराज नगर सीट पर जीत मिली। द्रमुक नेता के. रथमणि की जून में मृत्यु हो जाने के बाद विक्रावंडी उपचुनाव की घोषणा की गई थी, जबकि नंगुनेरी सीट कांग्रेस नेता एच वसंत कुमार के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी।

मुख्यमंत्री के पलनिस्वामी ने कहा कि द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने झूठे वादों के दम पर लोकसभा चुनाव जीता है। द्रमुक-नीत गठबंधन ने अप्रैल-मई में राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 38 पर जीत दर्ज की थी।

तेलंगाना

सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने उपचुनाव में कांग्रेस से हुचुरनगर सीट पर कब्जा जमाने

में सफलता हासिल की। यह सीट कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख एन उत्तम कुमार रेड्डी के लोकसभा के लिए चुने जाने से की वजह से खाली हो गई थी।

बिहार

बिहार में, सत्तारूढ़ भाजपा-नीत राजग ने पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन किया जिसे 12 महीने में विधानसभा चुनाव से पहले सेमी-फाइनल के तौर पर करार दिया गया था। हालांकि लोजपा के प्रिंस राज ने समस्तीपुर लोकसभा सीट पर आसानी से कब्जा किया है। यह सीट लोजपा के सांसद राम चंद्र पासवान के निधन से खाली हुई थी। बिहार में, राजग ने 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर सीट दर्ज

उपचुनाव में किसे मिली शह और मात

विधानसभा उपचुनाव			विधानसभा उपचुनाव		
राज्य	उपचुनाव की सीटें	जीत/आगे चल रहीं पार्टियां	राज्य	उपचुनाव की सीटें	की सीटें चल रहीं पार्टियां
अरुणाचल प्रदेश	1	स्वतंत्र	पुदुच्चेरी	1	कांग्रेस 1
असम	4	भाजपा 3/ एआईयूडीएफ 1	पंजाब	4	कांग्रेस3/अकाली
बिहार	5	राजद 2/जद-यू।/ एआईएमआईएम 1/आईएनडी 1	राजस्थान	2	कांग्रेस1/रालोपा।
छत्तीसगढ़	1	कांग्रेस 1	सिक्किम	3	भाजपा2/एसकेएम।
गुजरात	6	भाजपा3/कांग्रेस 3	तमिलनाडु	2	अन्नाद्रमुक 2
हिमाचल प्रदेश	2	भाजपा2	तेलंगाना	1	टीआरएस।
केरल	5	कांग्रेस 2/सीपीएम2/ आईयूएमएल 1	उत्तर प्रदेश	11	भाजपा7/सपा2/अपना दल1/बसपा।
मध्य प्रदेश	1	कांग्रेस 1	दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव		
मेघालय	1	युडीएफ 1	समस्तीपुर सीट (बिहार)	सातारा सीट (महाराष्ट्र) पर राकांपा का कब्जा	
ओडिशा	1	बीजद 1	लोजपा ने जीती		

की थी। उपचुनाव में जद (यू) ने पांच विधानसभा सीटों में से 4 पर कब्जा जमाया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए अच्छी खबर है। वहां पार्टी ने 11 सीटों में से सात पर बढ़त बनाई है जबकि सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने एक सीट पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी (सपा) सत्तारूढ़ भाजपा से जैदपुर सीट छीनने में सफल रही। खबर लिखे जाने तक सपा रामपुर में और बसपा जलालपुर में आगे चल रही थीं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मंडावा सीट पर जीत हासिल की जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) खिनसर सीट बरकरार रखने में कामयाब रही।

सिक्किम

पी एस गोलय के नाम से चर्चित सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की चुनावी जीत से उनकी हैसियत मजबूत हुई है। वह पहले ही सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके हैं। 51 वर्षीय एसकेएम प्रमुख ने मई में चामलिंग के सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 24 वर्षीय शासन को समाप्त करने में सफलता हासिल की थी। मई में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने राज्य में 32 विधानसभा सीटों में से 17 पर अपना कब्जा जमाया था। पांच महीने पहले चामलिंग ने इसी सीट पर एसकेएम के खड़का बहादुर राय को 2,899 मतों से हराया था।